राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 270 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार , 01 अप्रैल 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

फ्रांस से भारत पहुंच रहे 3 राफेल

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को और ताकतवर बनाने में जुटी है। तीन राफेल लड़ाकू विमानों की खेप आज फ्रांस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। इसी के साथ भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है। तीन राफेल लड़ाकू विमान आज शाम अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। ये तीनों विमान विमान फ्रांस से भारत की दूरी बिना रुके तय करेंगे।

एक दिन में नए मामलों की रफ्तार घटी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारत में कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों में थोड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 53 हजार 480 नए मामले दर्ज किए गए हैं तो वहीं इस दौरान 41 हजार 280 मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि, चिंता की बात यह है कि इस बीच मौत का आंकड़ा साढ़े तीन सौ पार कर गया है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से 354 लोगों की जान गई है। इसी के साथ अब भारत में कोरोना वायरस के कुल 1 करोड़ 21 लाख 49 हजार 335 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 14 लाख 34 हजार 301 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं।

सत्ता में आने पर अपने वादे पूरे करेगी कांग्रेस : राहुल

गुवाहाटी, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को गुवाहाटी में प्रख्यात कामाख्या मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। मंदिर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा जैसी नहीं है, कांग्रेस चुनावों के दौरान लोगों से किए वादे निभाती है। यह पूछे जाने पर कि अगर उनकी पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो वह क्या करेगी, इस पर उन्होंने कहा, हमने पांच चीजों की गारंटी दी है। कांग्रेस इन पांच वादों को कैसे पूरा करेगी, यह पूछने पर कांग्रेस नेता ने पूछा, आप जानते हैं कि वादे का मतलब क्या होता है हम भाजपा की तरह नहीं है, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं।

कार्टून

औद्योगिक विकास को दी जाए गति : केजरीवाल

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य की आज दिल्ली सचिवालय में बैठक कर समीक्षा की। समीक्षा बैठक में दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और डीएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक-एक कर सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे कार्य को तय समय सीमा के अंतर्गत पाए जाने पर संतोष जताया। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य को और तेज कर औद्योगिक विकास को गति दी जाए। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, उन्हें तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए, ताकि दिल्ली में औद्योगिक विकास की गति और तेज हो सके।

सीएम केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बैठक कर डीएसआईआईडीसी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज और सड़क आदि के चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। बैठक में डीएसआईआईडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंगोलपुरी इंस्ट्रीयल एरिया, पटपड़गंज इंस्ट्रीयल एरिया, मायापुरी इंस्ट्रीयल एरिया, उद्योग नगर इंस्ट्रीयल एरिया, ओखला इंस्ट्रीयल एरिया, झिलमिल इंस्ट्रीयल एरिया, झंडेवालान इंस्ट्रीयल एरिया, लॉरेंस रोड इंस्ट्रीयल एरिया, कीर्ति नगर इंस्ट्रीयल एरिया, जीटी करनाल रोड इंस्ट्रीयल एरिया, भोरगढ़ इंस्ट्रीयल एरिया, बवाना फेस टू इंस्ट्रीयल एरिया में चल रहे ड्रेनेज और सड़क के कार्य की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में डीएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने एक-एक कर सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य की मौजूदा स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने ड्रेनेज और सड़क आदि विकास कार्य को पूरा करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है, उसी के अनुसार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य चल रहे हैं, बल्कि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में तय समय सीमा में जितने विकास कार्य संपन्न होने चाहिए, उससे अधिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अभी तक 85 प्रतिशत से अधिक विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह, उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर रोड और ड्रेनेज का कार्य 99 प्रतिशत पूरा हो चुका हैं और जल्द ही बाकी कार्य भी पूरे कर लिए जाएंगे। ओखला औद्योगिक क्षेत्र के अंदर रोड का कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि कुछ कार्य 65 प्रतिशत से अधिक पूरे किए जा चुके हैं।

सीएम केजरीवाल ने औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य को और गति दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली के अंदर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी तरह का विकास कार्य हो, उसे यथा शीघ्र पूरा किया जाए और किसी भी तरह की अड़चन न आने दी जाए, ताकि फैक्ट्री संचालकों और वहां आने-जाने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऑपरेशन लोटस मामले में कर्नाटक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को झटका, हाई कोर्ट ने जांच को दी हरी झंडी

बेंगलुरु । ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच कराने की मंजूरी दे दी है। जेडीएस के नेता नगर गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इसी याचिका को खारिज करते हुए जांच की मंजूरी दे दी है।

बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह एक जगह संबोधित करते हुए सुनाई दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि कई बीजेपी नेताओं के निर्देश पर ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। इन बीजेपी नेताओं में खुद अमित शाह भी शामिल थे।

इसके अलावा, तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी एक बातचीत का ऑडियो क्लिक जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने जेडीएस विधायक को पैसे और पद देने का लालच दिया है। एफआईआर में दो बीजेपी विधायकों-शिवनागौड़ा नाईक और प्रीतम गौड़ा का भी नाम था। दावा किया गया था कि दोनों सर्किट हाउस में मौजूद थे जब शरण गौड़ा ने येदियुरप्पा से मुलाकात की थी।

बता दें कि कर्नाटक के 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस-जेडीएस ने गठबंधन किया था। इसके बाद नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका था। साल 2019 में कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार को गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बने थे।

कर्नाटक सरकार में बगावत-

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक ओर जहां ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी है। ईश्वरप्पा ने सीएम येदियुरप्पा पर उनके कामकाज में हस्तक्षेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

कर्नाटक सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ईश्वरप्पा ने राज्यपाल वजुभाई वाला को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की शिकायत की है। उन्होंने येदियुरप्पा पर कर्नाटक (व्यापार का लेन-देन) नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भी भेजी है।

मंत्री ईश्वरप्पा का आरोप है कि येदियुरप्पा ने उनके विभाग से बिना उनकी सहमति लिए हुए 774 करोड़ रुपये का आवंटन किया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक जिले के लिए अपने मंत्रालय के बजट से 65 करोड़ रुपये आवंटित किए और 29 अन्य जिलों की उपेक्षा की। बता दें कि ईश्वरप्पा और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एक समय काफी करीबी माने जाते थे। दोनों के बीच में रिश्ते तब बदल गए जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए कई नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी थी। इसके बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी।

कृषि कानूनों पर गठित समिति ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने तीन नए कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। समिति के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की है, लेकिन यह नहीं बताया है कि इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं। तीन सदस्यीय समिति के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री अनिल घनवात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में 19 मार्च को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमिटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मार्च तक का वक्त दिया गया था। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया था।

2022 से पहले बोडो समझौते में किया हर वादा पूरा करेगी भाजपा : शाह

चिरांग, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को असम के चिरांग में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा भाजपा 2022 तक बोडोलैंड समझौते को पूरी तरह लागू करेगी। शाह ने कहा हमने बोडोलैंड समझौता किया और समझौते के तहत दो तिहाई वादे छह महीने में पूरे कर दिए हैं। कांग्रेस कभी भी हिंसा, आतंकवाद और आन्दोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी।

उन्होंने कहा कि हमने डबल इंजन सरकार के माध्यम से असम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है।

शाह ने बदरुद्दीन अजमल के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा राहुल बाबा आजकल एक पर्यटक के तौर में असम में हैं। वह कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। आप मुझे बताएं कि क्या अजमल असम की पहचान है या भूपेन हजारिका, उपेंद्र नाथ और शंकर देव। बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान नहीं हो सकता है।

शाह ने कहा कि सालों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, युवा और पुलिसकर्मी मारे जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको सब को लड़ाने में आनंद आता है। आपने पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाई, 5 साल में हमने असम को आतंकवाद से मुक्त कर दिया।

राज्य में आ रही बाढ़ के बारे में बोलते हुए पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि राज्य बाढ़ से मुक्त हो। हमारे संकल्प पत्र में हमने अगले 5 वर्षों में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान एक अप्रैल को होगा, जबकि 6 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे।

पाक आतंकी को भारत में हमलों की साजिश रचने के लिए 10 साल कठोर कारावास

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने दिल्ली समेत भारत के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पटियाला हाउस अदालत में एनआईए मामलों के विशेष न्यायाधीश ने पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी बहादुर अली को आईपीसी, यूए(पी) कानून, शस्त्र काननू, विस्फोटक कानून, विस्फोटक सामग्री कानून, विदेशी कानून और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी कानून की धाराओं में सजा सुनाई। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुमार्ना भी लगाया। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2016 में दर्ज यह मामला पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने से जुड़ा है।

उन्होंने बताया कि साजिश के तहत अली अपने दो साथियों अबू साद और अबू दर्दा के साथ मिलकर गैरकानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसा ताकि दिल्ली समेत भारत के अलग-अलग स्थानों पर आतंकवादी हमले कर सके। इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित लश्कर के आकाओं के इशारे पर भारत में घुसपैठ की। उन्होंने बताया कि अली को कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान अली ने आतंकवादी संगठन में भर्ती, लश्कर के विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, हथियार चलाने के लिए आतंकवादियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण, लश्कर के आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए उकसाने और पीओके में लश्कर के लॉन्चिंग पैड की जानकारियों का खुलासा किया। एनआईए ने जनवरी 2017 में अली के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। बाद में लश्कर-ए-तैयबा के दो अन्य पाकिस्तानी आतंकवादियों साद और दर्दा को कुपवाड़ा में फरवरी 2017 में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। एनआईए अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान अली के दो साथियों जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आरोपपत्र में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

भारत सुरक्षा परिषद में मतभेदों को कर रहा दूर

न्यूयॉर्क, (एजेंसी)। भारत ध्रुवीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सेतु का काम कर रहा है, मतभेदों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, परिषद के बयानों को दिशा देने में मदद कर रहा है, अफगानिस्तान और म्यांमा पर चर्चा और सीरिया में मानवीय संकट को ध्यान में रखकर वृहद बैठक पर जोर दे रहा है और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने कही। पंद्रह सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन के तीन महीने पूरे कर रहे भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद की चचाओं में अनूठा परिप्रेक्ष्य लाने में सफल रहा है। तिरुमूर्ति ने कहा, आप चाहें तो इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। यह बहुत गहन अवधि रही है।

उन्होंने रेखांकित किया कि भारत ऐसे समय में सुरक्षा परिषद सदस्य बना है जिसमें गत समय में ध्रुवीकरण हुआ है। तिरुमूर्ति ने कहा, ध्रुवीकरण अब भी दिखाई देता है, भारत सुरक्षा परिषद में मतभेदों को दूर करने में सेतु की तरह काम कर रहा है। हम सभी मुद्दों पर सदस्यों के साथ सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। हमारी बात का सम्मान होता है और हमारे योगदान को स्वीकार किया जाता है। तिरुमूर्ति ने जोर देकर कहा, परिषद के लिए एक सुर में बोलना महत्वपूर्ण है बजाय बिल्कुल ही नहीं बोलना। उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया जब भारत ने परिषद में नतीजे लाने में मदद की। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ने विभिन्न मुद्दों पर अपना परिप्रेक्ष्य लेकर आया। म्यांमा पर सुरक्षा परिषद के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अलग-अलग नजरिये को एक साथ लाकर इस बयान को अधिक सृजनात्मक और मुद्दे के समाधान में सहायक बनाने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करते हुए भारत ने परिषद के अफगानिस्तान पर बयान को स्वरूप देने में मदद की जिसमें बढ़ती हिंसा को लेकर हमारी चिंताओं और लक्षित हत्याओं के मुद्दे के साथ महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके अफगानिस्तान एवं इलाके पर होने वाले असर पर विचार किया गया। तिरुमूर्ति ने कहा, अफगानिस्तान और उसकी स्थिरता एवं शांति में हमारे महत्वपूर्ण हित है। तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस प्रक्रिया में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है।

बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान आज

कोलकाता, (एजेंसी)। बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज होगा। बंगाल में दूसरे चरण के तहत चार जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है जबकि असम में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने शंतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक इस चरण में केंद्रीय बलों की कुल 800 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस चरण में बंगाल में 75,94,549 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके 171 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य तय करेंगे। इनमें 152 पुरुष उम्मीदवार जबकि केवल 19 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए कुल 10,620 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। असम में दूसरे चरण के तहत 345 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद होगा। इनमें 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरे चरण के तहत हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में गुरुवार को वोटिंग होगी। इस संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यही नहीं एक हेलीकॉप्टर से इलाके में निगरानी भी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं और लोग बिना किसी डर के मतदान कर सकें। इसलिए बाहर के लोगों को जो नंदीग्राम के मतदाता नहीं हैं उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। अकेले इस निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय बलों की 22 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इसमें कुल 355 मतदान केंद्र हैं।

संक्षिप्त समाचार

बाइडन प्रशासन ने शिनजियांग में चीनी कार्रवाई को बताया नरसंहार, उइगरों के खिलाफ हिंसा पर फटकार

वाशिंगटन । चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच, बाइडन प्रशासन ने मंगलवार (स्थानीय समय) को शिनजियांग में उइगर मुस्लिम और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को नरसंहार घोषित किया। मानवाधिकार प्रथाओं पर 2020 की रिपोर्ट जो चीन ने मंगलवार को जारी किया। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि शिनजियांग में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगर और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ मानवता के खिलाफ नरसंहार और अपराध हुए। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि माइकल पोम्पिओ ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के विनाशकारी दिनों के दौरान शिनजियांग में आधिकारिक तौर पर नरसंहार की घोषणा की थी। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी सुनवाई के दौरान पोम्पिओ के आकलन की पुष्टि की। मंगलवार की अमेरिकी रिपोर्ट में शब्द का समावेश आधिकारिक अमेरिकी सरकार के आकलन के रूप में दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से बताता है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उइगरों के खिलाफ अपराध में दस लाख से अधिक नागरिकों की स्वतंत्रता की मनमानी कैद या अन्य गंभीर वंचित शामिल हैं। मजबूर नसबंदी, मजबूर गर्भपात, और चीन के जन्म नियंत्रण नीतियों के अधिक प्रतिबंधक आवेदन; बलात्कार; बड़ी संख्या में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की यातना; जबरन मजदूरी कराना; और धर्म की स्वतंत्रता या विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आंदोलन की स्वतंत्रता पर ड्रैकोनियन प्रतिबंध लगाए गए।

विदेश विभाग ने कहा कि चीन के सरकारी अधिकारी और सुरक्षा सेवाओं ने अक्सर मानव अधिकारों का दुरुपयोग किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने अक्सर पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई हत्याओं के मामलों की जांच की घोषणा की, लेकिन पुलिस की खराबी या अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामों या निष्कर्षों की घोषणा नहीं की।

पश्चिमी देशों और चीन के बीच तनाव के बीच ये रिपोर्ट आई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बाद तनाव की हाल ही में वृद्धि शुरू हुई, उइगरों के खिलाफ अत्याचार के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए।

ब्राजील के विदेश मंत्री ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर हुई आलोचना के बाद दिया इस्तीफा!

ब्रासीलिया । ब्राजील के विदेश मंत्री एर्नेस्टो अराजो ने कोरोना वैक्सीन की कमी के मुद्दे को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर स्पूतनिक वैक्सीन सप्लाई को लेकर राजनयिक नाकामी के आरोप लगे थे, जिसके बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। ब्राजील की स्थानीय अखबार ब्राजील ओ ग्लोबो न्यूजपेपर के अनुसार मंत्री ने अपने फैसले के बारे में स्टाफ को जानकारी दी और राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा मैं सरकार के लिए, और मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता हूं। हालांकि, अभी तक उनके इस्तीफे की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ब्राजील की संसद में मंत्री पर आरोप था कि उन्होंने वैक्सीन के इलाज के प्रयासों को बर्बाद कर दिया। खबरों में कहा गया है कि पूर्व में मंत्री अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे और उनकी तरह ही चीन पर हमला बोलते थे। माना जा रहा है कि इसके चलते ही उनके देश को कोरोना वैक्सीन की शिपमेंट नहीं मिल पाई।

बता दें कि दुनिया में इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका है। वहीं ब्राजील में भी प्रत्येक दिन स्थिति खराब होती जा रही है। यहां पिछले कुछ दिनों में लगातार हर दिन तीन हजार से यादा मौतें दर्ज हुई है 27 मार्च को यहां 3,650 मरीजों की मौत हुई थी। जबकि 23 मार्च को 3,158 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी।

अफ्रीकी देश नाइजर में राष्ट्रपति भवन के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी, 30 मिनट तक चलती रहीं गोलियां

वाशिंगटन , एजेंसी। अफ्रीकी देश नाइजर में बुधवार को राष्ट्रपति भवन के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना हुई है. जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावर करीब आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे. यह घटना ऐसे समय हुई है, जब दो दिन बाद मोहम्मद बाजूम राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक फायरिंग की घटना स्थानीय समयानुसार तड़के करीब 3 बजे हुई और लगभग 30 मिनट तक गोलियां चलती रहीं.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे जाकर माहौल शांत हो पाया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कई वीडियो में गोलीबारी की आवाज को सुना जा सकता है. वीडियो में हालांकि स्थान और समय का अंदाजा नहीं लग पा रहा है. नाइजर सरकार ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.पिछले महीने फरवरी में राष्ट्रपति चुनावों में बाजूम की जीत के बाद से ही राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है. साथ ही हथियारबंद समूहों के हमले भी काफी यादा बढ़ गए हैं. पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद उस्मान ने चुनावों में हार के बाद परिणामों को मानने से इनकार कर दिया था. उन्होंने चुनावों में धांधली के भी आरोप लगाए थे. उन्होंने बुधवार को देश की राजधानी नियामे में अपनी ताकत दिखाने के लिए 'शांतिपूर्ण मार्च' का भी आह्वान किया था. मगर प्रशासन ने एक दिन पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया.

पिछले हफ्ते नाइजर की शीर्ष अदालत ने बाजूम की जीत पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति चुनावों को क्लीन चिट दे दी थी. इससे उनके 2 अप्रैल को शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया. बाजूम का शपथ ग्रहण इस मायने में भी खास है पहली बार पश्चिमी अफ्रीकी देश में लोकतांत्रिक सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और दूसरी पार्टी को सत्ता सौंपी है. पूर्व गृह मंत्री रहे बाजूम को पहले से ही पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मदू इसोउफोउ का उत्तराधिकारी माना जा रहा था. उन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ दिया था. दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक नाइजर में कई तख्तापलट की घटनाएं हुई हैं. पिछला तख्तापलट फरवरी, 2010 में हुआ था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति मामादोउ तान्जा को सत्ता गंवानी पड़ी थी.

म्यांमार में आम लोगों पर टूट रहा सेना का कहर, अब किए हवाई हमले, जान बचाने को हजारों थाईलैंड भागे

म्यांमार । म्यांमार में लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे आम लोगों पर सेना का कहर टूटना जारी है. अत्याचारों की हदें पार करते हुए इस पड़ोसी मुल्क में अभी तक 500 से यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं. ताजा घटना में सेना अब हवाई हमले पर उतर आई है. म्यांमार की सेना ने देश के पूर्वी हिस्से पर हवाई हमले किए. इसके बाद हिंसा की स्थिति गहरा गई. इन हमलों से जान बचाने के लिए अल्पसंख्यक करेन जाति के हजारों लोग सीमा पार करके शरण के लिए थाईलैंड पहुंचे. इस बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चन-ओचा ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने म्यांमार से आए लोगों को वापस जाने के लिए मजबूर किया. कहा जा रहा है कि बीते सप्ताह हवाई हमलों के बाद भागकर आए लोगों को वापस म्यांमार भेज दिया गया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपनी मर्जी से घर लौटे.

हवाई हमले में 6 की मौत– पूर्वी म्यांमार की स्थिति काफी खतरनाक हो रही है. वहां पर करेन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य राजनीतिक निकाय 'करेन नेशनल यूनियन' (केएनयू) के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख सॉ तॉ नी ने बताया कि मंगलवार को किए गए हवाई हमलों में छह नागरिकों की मौत हुई है और 11 जख्मी हुए हैं. म्यांमार की सेना के हमले के चलते केएनयू ने अपनी एक सशस्त्र इकाई के जरिए बयान जारी करके कहा, 'सेना सभी मोर्चों से हमारे क्षेत्र की ओर बढ़ रही है और उसने मुकाबला करने का संकल्प लिया है.'

अब तक 500 की मौत– म्यांमार की सेना ने फरवरी में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया था. इसके बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे. अब तक कम से कम 510 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. म्यांमार के 'असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रीज़नर्स' के मुताबिक, मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है और 2574 लोगों को हिरासत में लिया गया है. शनिवार को 100 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद मंगलवार को प्रदर्शन जारी रहा.

अमेरिका समेत 14 देशों ने डब्ल्यूएचओ की कोरोना वायरस की उत्पत्ति संबंधी रिपोर्ट पर जताई चिंता

वाशिंगटन । अमेरिका और जापान समेत 14 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट पर चिंता जताई है जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके इंसानों में फलने का विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ के साथ चीन ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में डब्ल्यूएचओ ने इसकी उत्पत्ति और इंसानों में फैलने की जांच के लिए अपनी दस सदस्यों की टीम चीन के वुहान शहर में भेजी थी। इस टीम ने वहां पर सी-फूड मार्केट समेत दूसरी जगहों की जांच की और साथ ही लोगों और चीनी विशेषज्ञों से भी इस संबध में बात की थी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि उन्हें जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके दम पर ये कहा जाए कि ये वायरस चीन की लैब से लीक हुआ था।

उन्होंने ये भी कहा कि ये वायरस चमगादड़ के जरिए इंसान में आया लेकिन कैसे इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इसमें ये भी कहा गया कि वायरस के लैब से लीक होने की बातें बेबुनियाद हैं क्योंकि सभी लैब अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। लेकिन अब इसी रिपोर्ट में इन 14 देशों ने सवाल खड़ा कर दिया है। इनका कहना है कि संगठन ने अपनी रिपोर्ट को सही तरह से तैयार नहीं किया है। इसमें ऑरिजनल डाटा और सैंपल को शामिल नहीं किया गया है। इन देशों से संगठन द्वारा रिपोर्ट में देरी किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रिपोर्ट को मंगलवार को जारी किया था।

जिन देशों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है कि उनमें अमेरिका, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्तोनिया और इजरायल भी शामिल हैं। इन सभी ने एक बयान में कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं साथ ही जो संगठन द्वारा इस महामारी को खत्म करने के जो कदम उठाए हैं वो उसके समर्थन में हैं। इतना ही नहीं वो ये वायरस की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये दूसरे देशों में फैलता चला गया इसको भी समझते हैं।

इसके बावजूद इन सभी देशों ने जिस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है उसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। जापान, लातविया, लिथुवानिया, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवानिया और ब्रिटेन ने भी अन्य देशों द्वारा दिए गए इस बयान को सही बताते हुए इस पर अपनी सहमति दी है।

इन सभी देशों का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के विशेषज्ञों ने चीन के वुहान में 14 जनवरी से 10 फरवरी के बीच जो रिव्यू किया वो इस बात को जानने का पहला कदम होगा कि ये वायरस कैसे आया और कैसे फैला। अलजजीरा के मुताबिक संगठन के महानिदेशक टैड्रोस एधनोम घेबरेयसस ने विशेषज्ञों से मांग की है कि इस रिपोर्ट पर दोबारा गौर कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस एसेसमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है। उन्होंने ये बातें न्यूज ब्रिफिंग के दौरान कही हैं। इस रिपोर्ट में टीम इस नतीजे पर जरूर पहुंची है कि वायरस के लैब से निकलने की बात जो कही जा रही थी वो पूरी तरह से मनघंड़त हैं। इसके बाद भी इन सभी तथ्यों की दोबारा पड़ताल करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो इसके लिए अपने विशेषज्ञों की टीम को तैनात करने के लिए तैयार हैं।

आपको बता दें कि इस महामारी के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने चीन की कड़ी निंदा की है। इन्होंने चीन पर इसको फैलाने या उसके जरिए फैलने का अंदेशा जताया है। दुनिया के कई देशों ने इसमें चीन की भूमिका को संदिग्ध माना है और कहा है कि इस महामारी की वजह से दुनिया के करोड़ों लोग बीमार हुए हैं जबकि तीस लाख लोगों की मौत हो चुकी है।

ताइवान के विदेश मंत्रालय में चीनी साइबर हमले कई गुना तक बढ़े, चिंता बढ़ी

ताइपे । ताइवान के विदेश मंत्रालय में चीनी साइबर अटैक्स पिछले कुछ समय में कई गुना बढ़े हैं। एक स्रोत का हवाला देते हुए प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में ताइवान के विदेश मंत्रालय के कंप्यूटर सिस्टम को लक्षित करने वाले चीनी साइबर अटैक्स की संख्या 2018 में हमलों की संख्या से लगभग 39 गुना अधिक रही।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल औसतन 2,100 हमले हुए और 2018 में कुल 20,000 हमलों से साथ अब तक लगभग 770,000 हमले किए जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि सूचना सुरक्षा अधिकारियों ने चीनी साइबर हमले के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है क्योंकि वे भी अधिक परिष्कृत हो गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल, विदेश मंत्रालय ने अपने सिस्टम की सभी जांच और स्कैन की अधिक बारीकी से निगरानी करना शुरू कर दिया। 2020 में किए गए कुल हमलों में से, लगभग 410,000 ताइवान विदेश मंत्रालय के कंप्यूटरों के स्कैन और जांच से जुड़े थे और 150,000 के करीब इसकी ई-मेल प्रणाली में सेंध लगाने के प्रयास से थे।

यह रिपोर्ट तब आई है जब 10 चीनी युद्धक विमानों ने सोमवार को ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया, अकेले मार्च में इस तरह की घुसपैठ कई बार की जा चुकी है। बता दें कि वायु रक्षा पहचान क्षेत्र प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हैं जो देशों को उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का पता लगाने में मदद करती हैं।

बता दें कि चीन, ताइवान पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करता है। चीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित लगभग 24 मिलियन लोगों के देश पर वह राज करना चाहता है। जबकि दोनों पक्ष सात दशकों से अधिक समय से अलग-अलग देश के रूप में हैं। दूसरी ओर, ताइवान ने अमेरिका सहित लोकतांत्रिक देशों के साथ सामरिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया है, जिसका बीजिंग द्वारा बार-बार विरोध किया गया है।

जावा सागर में क्रैश हुए श्रीविजय एयर जेट का मिला कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, पायलटों की बातचीत की मिलेगी जानकारी

इंडोनेशिया । इंडोनेशिया के जावा सागर में जनवरी में क्रैश हुए श्रीविजय एयर जेट के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को ढूंढ़ लिया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इंडोनेशियाई नौसेना के गोताखोरों ने विमान के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को ढूंढ़ा. इस विमान हादसे में क्रू मेंबर्स समेत सभी 62 लोगों की मौत हो गई थी. विमान के क्रैश होने के बाद कई हफ्तों तक वॉयस रिकॉर्डर को ढूंढ़ने का प्रयास किया गया था.

परिवहन मंत्री बुदी करिया सुमादी ने कहा कि गोताखोरों ने लगभग रात 08.00 बजे कॉकपिट रिकॉर्डर को बरामद कर लिया. गोताखोरों ने मंगलवार रात इसे उसी जगह से बरामद किया, जहां दुर्घटना के तीन दिन बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बरामद किया गया था. रिकॉर्डर के भीतर मौजूद जानकारी को तुरंत जारी नहीं किया गया. हालांकि, इस डिवाइस के जरिए जांचकर्ताओं को यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि 9 जनवरी को जकार्ता से उड़ान भरने के तुरंत बाद बोइंग 737-500 भारी बारिश में समुद्र में कैसे क्रैश हुआ था.

यदि वॉयस रिकॉर्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो इससे जांचकर्ताओं को बड़ी मदद मिल सकती है. उन्हें इसके जरिए ये पता चल सकता है कि पायलट विमान को क्रैश होने के बचाने के लिए क्या कर रहे थे या क्या करने में असफल रहे.

खोजकर्ताओं ने जकार्ता के उत्तर में, हजारों द्वीप श्रृंखला में लंकांग और लाकी द्वीपों के बीच एक क्षेत्र से विमान के पुर्जे और मानव अवशेष बरामद किए हैं. फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने सैकड़ों मापदंडों को ट्रैक किया, जिसमें दिखाया गया कि विमान को कैसे उड़ाया जा रहा था.

विमान हादसे के लगभग दो सप्ताह बाद अधिकतर बचाव प्रयास समाप्त हो गए. लेकिन कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की लापता मेमोरी यूनिट के लिए एक सीमित खोज जारी रही, जो स्पष्ट रूप से दुर्घटना के दौरान डिवाइस के अन्य हिस्सों से टूटकर अलग हो गया था. वॉयस रिकॉर्डर को जकार्ता ले जाया गया है, जहां दुर्घटना की जांच की देखरेख करने वाली राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति को इसे सौंपा गया है.

विमान हादसे ने खड़े किए कई सवाल– गौरतलब है कि 26 साल पुराना विमान दिसंबर में कमर्शियल उड़ानों के फिर से शुरू होने से पहले तक नौ महीने से एयरपोर्ट पर ही खड़ा था.

9 जनवरी को हुए इस विमान हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया. इंडोनेशिया में ये सवाल और भी तेजी से उठने लगा, क्योंकि यहां विमान हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. दूसरी ओर, श्रीविजय एयर में पहले के समय में केवल मामूली दुर्घटनाएं हुई थीं. वहीं, 2018 में लायन एयर द्वारा संचालित बोइंग 737 मैक्स 8 जेट जकार्ता में हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें 189 लोग मारे गए.

एशियाई लोगों पर बढ़ते हमले से बाइडन नाराज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश

वाशिंगटन । दुनिया में तेजी से बढ़ रहे एशियाई मूल के लोगों पर हमलों ने अमेरिकी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इन मामलों पर नाराजगी जताते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हम एशियन-अमेरिकन लोगों के साथ बढ़ती हिंसा पर चुप नहीं रह सकते हैं। इसीलिये आज मैं हिंसा के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठा रहा हूं। उन्होंने न्याय विभाग से भी इस पर तत्काल योजना बनाकर काम करने के लिए कहा गया है। बाइडन ने कहा कि एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा और विदेशी लोगों को नापंसद करना गलत है, यह रुकना चाहिए।

उन्होंने इस दौरान न्याय विभाग के अंतर्गत कोविड 19 इक्विटी टास्क फोर्स कमेटी का भी गठन किया। यह कमेटी कोरोना को लेकर दी जाने वाली राहतों में यह सुनिश्चित करेगी कि इसमें विदेशी मूल का होने के कारण किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। हिंसा के मामलों पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया कि किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने कहा कि मैं और हमारे राष्ट्रपति इन मामलों पर चुप नहीं रहेंगे। एशियाई मूल के लोगों के प्रति हिंसा को रोकने के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि आने वाले दिनों में एशियन-अमेरिकन लोगों से राष्ट्रपति मिलेंगे और उनसे इस संबंध में सुझाव लिए जाएंगे कि वे इस समस्या के हल में किस तरह से समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

अमेरिका में अश्वेत फ्लायड हत्याकांड की सुनवाई शुरू

अमेरिका के चर्चित अश्वेत जॉर्ज फ्लायड की हत्या के आरोप में अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को वह वीडियो दिखाया गया, जो दुनियाभर में वायरल हुआ। उसमें एक पुलिसकर्मी फ्लायड की गर्दन को पैरों से जकड़कर दबा रहा है। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि पुलिसकर्मी डेरेक शॉविन ने फ्लायड को जिस तरह से मारा है, ऐसी स्थिति में यह मामला अमेरिका के न्याय तंत्र की एक परीक्षा है।

60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक देगा चीन, नहीं दिया जाएगा 'बूस्टर'

बीजिंग एजेंसी । चीन ने 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 रोधी टीका लगाने की अपनी योजना की अंततः घोषणा कर दी है. चीन के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सिर्फ एक ही खुराक लगाई जाएगी और 'बूस्टर' नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसकी सिफारिश फिलहाल नहीं की गई है. मीडिया में आई एक खबर में मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई.

सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) के मुताबिक चीन में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 रोधी टीके दिए जा चुके हैं लेकिन ये सिर्फ 18 से 59 साल के लोगों को दिए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि 59 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जाना अभी बाकी है.

नाबालिगों को करना होगा इंतजार

चीन यह भी कहता है कि उसने करीब 10 करोड़ टीके विदेश भेजे हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को टीका लगाना अभी बाकी है. हाल में जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 26 करोड़ से ज्यादा है. एनएचसी ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सोमवार को अपने पहले आधिकारिक दिशानिर्देश में बताया कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा.

एनएचसी के मुताबिक मौजूदा नैदानिक अनुसंधानों के आंकड़ों ने नजर आता है कि टीके वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह भी कहा गया कि कोविड-19 टीकों की 'बूस्टर' खुराक दिए जाने की सिफारिश अभी नहीं की गई है. दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए फिलहाल टीकाकरण की सिफारिश नहीं की गई है.

बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने बीते दिनों कोरोना उत्पत्ति की जांच करने के लिए वुहान का दौरा किया था, जहां 2019 में कोरोना का पहला मामला सामने आया था. मंगलवार को इस टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की. रिपोर्ट में कोरोना के स्रोत का पता नहीं चल सका है. रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा कि सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आगे और रिसर्च किए जाने की जरूरत है.

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि हमें विज्ञान का पालन करना जारी रखना चाहिए और कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए. मीडिया संस्थानों को मिली डब्ल्यूएचओ की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह रिपोर्ट सवाल उठाते हुए हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है जिसका समाधान आगे के अध्ययनों से होगा.

दक्षिण अफ्रीका ने ईस्टर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

जोहानसबर्ग । दक्षिण अफ्रीका ने शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने घोषणा करते हुए बताया कि ईस्टर के मौके पर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है और साथ ही धार्मिक और सामाजिक समारोहों में एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। बताया गया कि कोरोना के नए मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं, ऐसे में छुट्टियों के दौरान सीओवीआईडी -19 के मामले और अत्याधिक न बढ़ने पाएं। रामफोसा ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, शराब पीकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने को ध्यान में रखते हुए हम ईस्टर सप्ताहांत पर कुछ पाबंदियां लगाएंगे। उन्होंने कहा कि शराब की खुदरा बिक्री पर सोमवार से सोमवार तक प्रतिबंध रहेगा। बार और रेस्तरां मादक पेय बेच सकेंगे, लेकिन रात 11 बजे तक सब बंद करना होगा।

इनडोर धार्मिक समारोहों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति दी जाएगी, जबकि 500 लोगों को बाहरी कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी जाएगी।

कंगाली और महंगाई से बेहाल पाकिस्तान भारत से मंगाएगा कॉटन-चीनी, इमरान सरकार ने हारकर व्यापार को दी मंजूरी

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाले पाक कपड़ा मंत्रालय ने भारत से कॉटन और चीनी के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कैबिनेट समिति से अनुमति मांगी थी. बुधवार को इसे समिति द्वारा मंजूर कर दिया गया है.

इस तरह पाकिस्तान में कच्चे माल की कमी से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को भारत से कॉटन मिल पाएगा. समिति ने भारत से चीनी का आयात करने को भी मंजूरी दी है. इसे नई दिल्ली संग रिश्तों को सुधारने की दिशा में इस्लामाबाद का प्रमुख कदम माना जा रहा है.

पड़ोसी मुल्क के 'पाकिस्तान मंत्रिमंडल आर्थिक समन्वय समिति' ने 30 जून 2021 तक भारत से चीनी और कॉटन का आयात करने के लिए अपनी मंजूरी दी. हालांकि, भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. ऐसे में ये देखना होगा कि भारत की इस पर क्या टिप्पणी होती है. गौरतलब है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली हो चुका है. देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होने से पड़ोसी मुल्क कंगाली की हालत में पहुंच गया है.

अब जानवरों को भी लगेगा कोरोना वायरस का टीका, रूस ने बनाई दुनिया की पहली वैक्सीन

मॉस्को । कोरोना वायरस का कहर मनुष्यों के अलावा जानवरों को भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में रूस ने अब जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है। जानवरों के लिए बनाई गई इस नई वैक्सीन का नाम ष्टड्डह्लठ्ठद्ब1ड्डष्-ष्टश्1 है। देश के कृषि मामलों पर नजर रखने वाली संस्था रोजेलखोनाजोर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है।

बता दें कि रूस में पहले से ही मनुष्यों के लिए कोरोना वायरस की तीन टीके उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय वैक्सीन स्पुतनिक वी है। मास्को ने दो अन्य वैक्सीन एपिवैककोरोना और कोविवैक को भी आपातकालीन स्वीकृति दी है।

संस्था ने बताया कि जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन कार्निवैक-कोव रोजेलखोनाजोर की ही एक इकाई द्वारा विकसित की गई है। रोजेलखोनाजोर के उप प्रमुख कोंस्टेंटिन सवेनकोव ने कहा कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। इसमें कुत्तों, बिल्लियों, आर्कटिक लोमड़ियों, मिंक, लोमड़ियों और अन्य जानवरों को शामिल किया गया था।

ट्रायल के परिणाम में यह बात सामने आई कि वैक्सीन जानवरों के लिए हानिरहित और अत्यधिक प्रतिरक्षात्मक है। जितने जानवरों को टीका लगाया गया था उन सबमें कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी विकसित हुई।

पाकिस्तान में 74 साल पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, पुनर्निर्माण और मरम्मत का चल रहा था काम

रावलपिंडी, एजेंसी । पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में स्थित 74 साल पुराने मंदिर में हमला किया गया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि बानी गाला थाने में इस संबंध में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पिछले महीने से इस मंदिर के पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था। इसके चलते मंदिर में फिलहाल पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहे थे। मंदिर में देवी-देवताओं की मूर्तियां भी नहीं थीं।

रावलपिंडी के उत्तरी जोन के सहायक सुरक्षा अधिकारी सैयद रजा अब्बास ने कहा कि 10 से 12 लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इससे मंदिर के बाहरी हिस्से में दरवाजों और सीढ़ियों को नुकसान पहुंचा है। निर्माण कार्य में भी बाधा आई है। मंदिर के प्रशासक ओम प्रकाश ने कहा कि इस घटना के बाद उनके घर के साथ ही मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू समुदाय ने पाकिस्तान सरकार से उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला कोई नई बात नहीं है। पिछले साल दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मौलवी के उकसावे पर भीड़ ने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया था। बाद में स्थानीय सरकार ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की घोषणा की थी। इसके अलावा हिंदुओं पर हमले और हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनके साथ जबरन निकाह की घटनाएं भी आम हैं।

अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत में दमकलकर्मी ने अदालत में किया सनसनीखेज खुलासा

मिनियापोलिस । अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ था। पुलिस इसे हादसा करार दे रही थी। हालांकि, अब इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिका में मिनियापोलिस की एक दमकलकर्मी ने मंगलवार को अदालत में बताया कि उसे अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मदद करने से रोक दिया गया था। वह बुधवार को फिर से अदालत में बयान दर्ज कराएंगी।

बता दें कि पिछले साल मई में श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन को फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबाने से रोकने वालों में से एक जिनेवी हन्सेन मंगलवार को यह याद करते वक्त रो पड़ी कि कैसे वह फ्लॉयड की मदद नहीं कर पाई। हन्सेन ने अदालत में जो बताया, उसे सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने बताया, वहां एक व्यक्ति को मारा जा रहा था। मैं अपने पूरी क्षमता के अनुसार चिकित्सा मुहैया करा सकती थी और इस इंसान ने ऐसा करने से मना कर दिया। कोर्ट में हन्सेन मंगलवार को गवाही देने वाले उन प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थीं जिन्होंने 25 मई को फ्लॉयड की मौत की घटना देखी थी। एक के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कैसे चौविन ने फ्लॉयड को छोड़ने की उनकी मिन्नतों को ठुकरा दिया। इनमें वह युवती भी शामिल थीं जिसने फ्लॉयड की गिरफ्तारी का वीडियो बनाया था, जिससे देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

18 वर्षीय डार्नेला फ्रेजियर ने कहा, उसे(चौविन) परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हम जो कह रहे हैं, वह उसकी परवाह नहीं कर रहा। फ्लॉयड तड़प रहा था, हम उसकी ममद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार फ्लॉयड ने दम तोड़ दिया।

गौरतलब है कि चौविन (45) पर नौ मिनट 29 सेकंड तक फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबाने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हो गई। चौविन के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप साबित होने पर उसे 40 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2020 पूर्वाग्रह से प्रेरित : डा. ए सूर्यप्रकाश

नई दिल्ली। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन डा. ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2020 पूर्वाग्रहों से प्रेरित है। इसमें भारत को नीचे तथा कई ऐसे देशों को लोकतंत्र में ऊंचे स्थान पर दिखाया गया है, जहां वाकई में लोकतंत्र भेदभाव होता है। उन देशों में तो धार्मिक व सामाजिक रूप से संवैधानिक स्तर पर भेदभाव किया जाता है। वह विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआइएफ) द्वारा 'लोकतंत्र को परिभाषित करना' विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार में देशभर से काफी संख्या में लोग जुड़े थे।

उन्होंने कहा कि इधर, कई ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टें आई हैं, जिनमें भारत के लोकतंत्र को लेकर आलोचना की गई है। जबकि विविधता से भरे भारत में हर किसी को अपनी पूजा पद्धति, भाषा व अभिव्यक्ति की आजादी जैसे अधिकार संविधान प्रदत्त है। बता दें, हाल ही में स्वीडन की एक संस्था की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में लोकतंत्र खोने की कगार पर है। इस वेबिनार की अध्यक्षता वीआइएफ के निदेशक डा. अरविंद गुप्ता कर रहे थे।

सूर्यप्रकाश ने कहा कि जिस डेनमार्क को इसमें बेहतर लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश बताया गया है, वहां चर्च को राज्य द्वारा प्रोत्साहित करने की संवैधानिक व्यवस्था है। इसी तरह स्वीडन का संविधान वहां के राजा को असाधारण शक्तियां देता है। अर्जेंटीना में राज्य और धर्म के संबंधों में घालमेल है, जबकि हमारे संविधान में हर किसी को अपने धर्म को मानते हुए पूजा पद्धति अपनाने की पूर्ण आजादी है। यहां सरकार के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक दलों की विविधता को कमजोर पड़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यहां केंद्र व राज्यों में छोटे-बड़े कुल 44 दल मिलकर सरकार चला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि संविधान की मूल भावना में बदलाव करने के लिए संसद के पास शक्तियां बेहद सीमित हैं। इसी तरह यहां भाषा की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रानिक व वेब मीडिया तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बड़ी स्वतंत्रता की मिसाल और क्या हो सकती है कि यहां रोजाना एंटी मोदी हैशटैग ट्रेंड होते हैं।

पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। दिल्ली में 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा के मामले में आरोपित पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नही हो सकी। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई को स्थगति करते हुए मामले को जिला व सत्र न्यायलय को ट्रांसफर कर दिया।

अब जिला जज तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन से जज करेंगे। क्योंकि जिस अदालत में यह मामला था उस कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो चुका है। इस बीच, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि सात सह-अभियुक्तों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत दी है। हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा है कि वह जल्द से जल्द सिद्धू द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब दे।

दिल्ली में मामा-भांजा गिरोह के दो बदमाश गिरफ्तार, काला चश्मा के जरिए पुलिस को लगा अहम सुराग

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका थाना पुलिस ने ऑटो में बैठे यात्रियों के साथ लूटपाट करने के आरोप में दो शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के साथ पूरा गिरोह लूटपाट में सक्रिय है। यह गिरोह मामा- भांजा गिरोह के नाम से जाना जाता है। दोनों आरोपितों के साथ एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों में सरजू राय व सोनू ठाकुर है। सरजू मूल रूप से बिहार के वैशाली जिला स्थित साहरिया गांव का रहने वाला है। वहीं सोनू बिहार के सीवान जिला स्थित बबनौली गांव का रहने वाला है।

अब इस मामले में पुलिस को सरजू राय के भांजे की तलाश है। पुलिस के अनुसार, 25 मार्च की रात एक शख्स ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि टीकरी बार्डर से उसे अपने घर जाना था। उसे पास ही में एक ऑटो खड़ा नजर आया। इसमें कुछ लोग बैठे थे। ऑटो चालक गीतांजलि जाने की बात कह रहा था। शिकायतकर्ता आटो में बैठ गया। कुछ देर बाद जब ऑटो एक सूनसान जगह पर पहुंचा तब उसमें सवार लोगों ने शिकायकर्ता के साथ लूटपाट शुरू कर दी। चाकू की नोंक पर उसका मोबाइल व नकदी उससे लूटा गया और पिटाई भी की गई। लूटपाट के बाद उसे वहीं छोड़ ऑटो पर सवार लोग फरार हो गए। शिकायतकर्ता से पुलिस को केवल इतना पता चला कि आरोपितों में से एक ने काला चश्मा पहन रखा था। सभी युवा थे। इस जानकारी के आधार पर मुंडका थाना प्रभारी गुलशन नागपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने करीब 250 ऑटो की जानकारी एकत्रित की व 600 लोगों से पूछताछ की । संयोग से पुलिस की मेहनत रंग लाई और पता चला कि हरियाणा के नंबर का एक ऑटो इलाके में चलता है। इसे मामा भांजा चलाते हैं। इसकी वारदात में संलिप्तता हो सकती है।

इसके बाद पुलिस ने पीवीसी मार्केट के पास पिकेट लगाकर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। यहां पुलिस तलाशी में जुटी थी कि एक ऑटो जिसपर दो लोग सवार थे, जिसमें से एक ने काले रंग का चश्मा पहन रखा था, नजर आए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन ऑटो चालक ने रुकने के बजाय रफ्तार तेज कर दी।

बाद में पुलिस ने पीछा किया और ऑटो का रोकने में कामयाबी पाई। ऑटो पर सरजू व सोनू सवार थे। दोनों के पास से एक चाकू व चार मोबाइल फोन पुलिस को बरामद हुए। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यह ऑटो सरजू राय के बहनोई का है। जिसे सरजू व उसका भांजा सुदीन राय चलाता है। दोनों इलाके में मामा- भांजा के नाम से जाने जाते हैं। पुलिस को पता चला कि जिस शख्स ने लूटपाट के दौरान चश्मा पहन रखा था वह सोनू राय है। ऐसा वह आकर्षक दिखने के लिए करता है। अब इस मामले में पुलिस को सुदीन राय की तलाश है।

मुठभेड़ के बाद पुलिस की पकड़ में आए नंदू गिरोह के दो बदमाश

पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद नंदू गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों का नाम धर्मेंद्र राणा व लकी है। मुठभेड़ के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चलाई गई। बदमाशों की ओर से तीन गोलियां चलाई गई।

तीनों गोली स्पेशल स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन कुमार को लगी। संयोग से वे बुलेटप्रूफ जैकेट पहने थे, जिनमें दो गोली जैकेट पर लगी और एक गोली उनके शरीर के नजदीक से गुजरी। वहीं बदमाशों को काबू करने के लिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। हालांकि ये गोलियां बदमाशों के आसपास से गुजर गईं। पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र व लकी क्षेत्र में एक के बाद एक वारदात अंजाम दे रहे थे। नजफगढ़ थाना के सामने सात मार्च को सुशील नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में भी ये शामिल थे। इसके अलावा 22 मार्च को उजवा में फौजी नामक व्यक्ति की हत्या में भी इनका नाम सामने आया था। इसके अलावा बिजवासन में एक केबल कारोबारी के कार्यालय में गोली चलाने के मामले में भी पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि आगे ये क्या क्या वारदात अंजाम देने वाले थे, इसका पता किया जा सके। मामले की तहकीकात जारी है।

अगले हफ्ते से नोएडा से अक्षरधाम का सफर होगा आसान

विपरीत दिशा में नहीं चलना होगा 700 मीटर

नई दिल्ली। अगले सप्ताह से नोएडा से मयूर विहार फेज-एक और मयूर विहार-एक से अक्षरधाम की ओर जाना हो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने यूपी लिंक रोड पर दो-तरफा क्लोवरलीफ तैयार कर दिया है। अगले सप्ताह से इसके चालू होते ही इसके जरिये लोग कर आवागमन कर सकेंगे। फिलहाल इस दूरी के लिए वाहन चालकों को एक किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता है। इन दोनों क्लोवरलीफ को पिछले पांच साल से बनाया जा रहा था। यह क्लोवरलीफ बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है, हालांकि, इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनने में अभी 2 साल का और समय लगेगा। मयूर विहार से अक्षरधाम और नोएडा से मयूर विहार के यातायात को बारापुला से मिलाने के लिए दो क्लोवर लीफ बने हैं। इनकी चौड़ाई साढ़े 7 मीटर है। अक्षरधाम की तरफ से बारापुला पर आने के लिए दो लेन की सड़क और नोएडा की तरफ से आने के लिए दो लेन की सड़क का निर्माण किया गया है। इससे लोग मयूर विहार फेज-एक के फ्लाईओवर पर न जाकर सीधे इस सड़क से बारापुला पर चढ़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त नोएडा की तरफ जाने और आने के फ्लाईओवर के साथ दीवार बनाई गई है, जिससे सुरक्षित यात्रा संभव हो सके। मयूर विहार एक से अक्षरधाम आने के लिए अभी पहले मयूर विहार से निकल कर यूपी लिक रोड पर करीब 700 मीटर विपरीत दिशा में नोएडा की ओर जाना पड़ता है। फिर अगले फ्लाईओवर के नीचे से यू-टर्न कर वापस आना होता है और फिर अक्षरधाम की ओर जाना होता है। नई व्यवस्था में मयूर विहार से निकलकर सामने की तरफ सीधे क्लोवरलीफ पर चढ़ेंगे और इसके माध्यम से यूपी लिक रोड पर आकर अक्षरधाम की ओर चले जाएंगे। इसी तरह अभी नोएडा से मयूर विहार आने के लिए यूपी लिक रोड पर मयूर विहार फेज एक से करीब एक किलोमीटर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर बने फ्लाईओवर के नीचे से यू-टर्न करके लौटना होता है। आना-जाना मिलाकर यह दूरी करीब दो किलोमीटर बैठती है। अब नई व्यवस्था में दो किलोमीटर का चक्कर लगाने से लोग बच जाएंगे, क्योंकि नोएडा की ओर से आकर मयूर विहार के सामने बने फ्लाईओवर से क्लोवरलीफ पर उतर कर मयूर विहार फेज- एक में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं, ये क्लोवरलीफ बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज-3 योजना का हिस्सा हैं। जिसका मकसद सराय काले खां की ओर से बारापुला होते हुए यूपी लिक रोड पर आने वाले यातायात को सुविधापूर्वक विभाजित करना है।

जिसे नोएडा की तरफ या अक्षरधाम की ओर जाना है या मयूर विहार फेज-एक में जाना है वह इन क्लोवरलीफ का उपयोग कर सके।

आयुर्वेदिक पौधों की दवा से होगा दुश्मन साबित हो रहे विलायती कीकर के जहर का उपचार

नई दिल्ली। सेंट्रल रिज पर स्थानीय प्रजातियों के लिए दुश्मन साबित हो रहे विलायती कीकर के जहर का उपचार अब आयुर्वेदिक पौधों की दवा से किया जाएगा। ये पौधे कीकर को चारों तरफ से घेरकर कुछ इस तरह अपनी गिरफ्त में लेंगे कि उसे भोजन-पानी मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में धीरे-धीरे यह विलायती कीकर खुद ही दम तोड़ना शुरू कर देगा। गौरतलब है कि सेंट्रल रिज पर 423 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला विलायती कीकर स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधों के जानलेवा साबित हो रहा है। इसके दुष्प्रभाव से स्थानीय प्रजातियों के पौधे पनप ही नहीं पाते। विलायती कीकर पानी का भी दुश्मन है। इसके असर से भूजल का स्तर भी गिरने लगता है। इसे फूलों में श्वांस रोग पैदा करने वाला भी माना जाता है। इन्हीं कारणों से विलायती कीकर को दिल्ली से साफ करने की रणनीति बनाई गई है। इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला अभियान सेंट्रल रिज के वन क्षेत्र में शुरू किया जाना है। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है, जो इस अभियान की पूरी निगरानी करेगी। पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा विलायती कीकर यूं तो दिल्ली में विलायती कीकर 7,777 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इसको साफ करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल रिज का 423 हेक्टेयर क्षेत्र चुना गया है। दिल्ली सरकार ने पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से यहां विलायती कीकर हटाकर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विलायती कीकर की तरह ही लैंटाना को भी साफ करने की योजना तैयार कर ली गई है। कैनोपी ओपनिंग तकनीक होगी कारगर कीकर के पौधे ऊपर से फैलकर धूप को नीचे आने से रोकते हैं। इससे स्थानीय प्रजाति के छोटे पौधों को धूप नहीं मिल पाती और वे विकसित भी नहीं हो पाते।

दिल्ली में अब मांस की दुकानों और रेस्तरां के बाहर झटका और हलाल का बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली। पूर्वी और दक्षिणी निगम के बाद उत्तरी निगम ने भी मांस की दुकानों पर झटका और हलाल लिखने के नियम को लागू कर दिया है। निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब मांस की दुकानों और रेस्तरां में यह प्रदर्शित करना जरूरी होगा वह झटका का मीट बेच रहे हैं या हलाल का। नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार खाने की वस्तुओं पर शाकाहार और मांसाहार को प्रदर्शित करना जरूरी है, वैसे ही अब मांस की बिक्री पर हलाल और झटका लिखना अनिवार्य कर दिया है। इस बाबत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने कहा कि हिंदू धर्म और सिख धर्म में हलाल मांस निषिद्ध है। इसलिए हमने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी ही। इसके तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सभी रेस्तरां, ढाबों और मीट की दुकानों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे हलाल या झटका का मांस परोसें या न बेचें। निगम के पार्कों में बोरवेल सीलिंग के मामले में सदन में चर्चा हुई। भाजपा पार्षदों ने पार्कों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर चल रही सीलिंग रोकने के लिए कहा। भाजपा पार्षद जोगीराम जैन ने कहा कि जब तक पार्कों में दिल्ली जल बोर्ड सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं कर देता तब तक पार्कों में बोरवेल सील नहीं होने चाहिए। इस पर महापौर ने निर्देश दिए कि कोई भी नया बोरवेल सील न किया जाए। वहीं, विभाग इसको लेकर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़े। उपचुनाव में दो सीटों से निवार्चित हुए आप पार्षदों ने सदन की बैठक में शपथ ली। उल्लेखनीय है कि सुनीता मिश्रा शालीमार बाग (पूर्वी) और रोहिणी सी से रामचंद्र विजयी होकर आए है। नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा अपनी भ्रष्ट नीतियों की वजह से उपचुनाव में हारी है। लोगों ने केजरीवाल की नीतियों से प्रेरित होकर आप उम्मीदवारों को जिताया है। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2021 पारित होने को लेकर निगम सदन में निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि बहुमत न होने की वजह से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा कि भाजपा चोर दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है, इसलिए यह संशोधन किया गया है। विकास गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की विश्वव्यापी प्रशंसा से डरकर केंद्र सरकार यह बिल लाई है। इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल तथा केंद्र की कठपुतली बना दिया गया है। उत्तरी निगम के महापौर जय प्रकाश ने बैठक शुरू होते ही जानकारी दी कि कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। निगम पर कर्मचारियों के वेतन का 822 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें से 550 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इससे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों को जनवरी तक का वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों का वेतन फरवरी तक जारी हो गया है।

दिल्ली के मौरिस नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार

पुलिस का कहना कि सुहैल का दो दिन पहले राहुल से झगड़ा हुआ था। उसने सुहैल की पिटाई कर दी थी। जिसका बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। राहुल अपने परिजनों के साथ सेंट स्टीफंस अस्पताल के पीछे शहीदी पार्क बगीची लेन में रहता था।

नई दिल्ली। मौरिस नगर में मंगलवार शाम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम राहुल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब्जीमंडी मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर घटना के चंद घंटे के अंदर आरोपित सुहैल उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना कि सुहैल का दो दिन पहले राहुल से झगड़ा हुआ था। उसने सुहैल की पिटाई कर दी थी। जिसका बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक राहुल अपने परिजनों के साथ सेंट स्टीफंस अस्पताल के पीछे शहीदी पार्क बगीची लेन में रहता था। परिवार में माता-पिता के अलावा दो बहन और एक भाई है। राहुल कमला मार्केट में ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति के साथ काम करता था। मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह किसी काम से मौरिस नगर आया था। तभी सुहैल ने पीछे से अचानक उसपर चाकू से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस ने उपचार के लिए राहुल को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौरस नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुहैल को गिरफ्तार कर लिया। वह न्यू चंद्रावल नगर में रहता है। वहीं, संगम विहार थाना पुलिस ने घर में घुसकर आभूषण चोरी करने के मामले में दो नाबालिग चोरों को पकड़ा है। आरोपितों के पास से सोने का हार, झुमके और कान की बालियां समेत कई आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 23 मार्च को संगम विहार थाना क्षेत्र में आभूषण चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपितों ने दिन के समय घर का ताला तोड़कर आभूषण चोरी कर लिए थे। जांच में जुटी पुलिस टीम को 28 मार्च को सूचना मिली कि एक किशोर कुछ दिनों से लगातार पार्टी कर रहा है। टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा और उसी की निशानदेही पर उसके दूसरे नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया।

दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत, लाइसेंस के लिए नहीं होना होगा परेशान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण में संपर्क करने की अनुमति देने का फैसला किया है। आवेदक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सारथी के माध्यम से फीस जमा करने के बाद सभी कार्य दिवस पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच संबंधित जोन के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सभी जोनल कार्यालयों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के संचालन के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं जिसके अंतर्गत वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इस आदेश से रोज़ाना बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर ई-रिक्शे की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऐसे हर वाहन की खरीद पर दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) के माध्यम से ऋण पर 5% ब्याज में छूट देने की भी योजना बना रही है। फिलहाल अभी इन फेसलेस सेवाओं का परीक्षण चल रहा है। विभाग अगले कुछ महीनों में 70 अन्य आवश्यक सेवाओं को 2 चरणों में फेसलेस सेवाओं के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये अति महत्वपूर्ण है। एक अन्य अहम फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने रविवार को भी आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया है।

धौलाकुआं से आजादपुर तक सिग्नल फ्री होगा लोगों को सफर

नई दिल्ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा अनुमति देने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) रिंग रोड को धौलाकुआं से आजादपुर तक सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी में जुट गया है। विभाग ने अंतिम अनुमति के लिए इस परियोजना को दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन (डीयूएसी) में लगाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीयूएसी में इस परियोजना को जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य इस योजना पर इस साल काम शुरू कर देने का है। यूटीपैक (यूनीफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर) इस परियोजना को 14 जनवरी को मंजूरी दे चुका है। इस परियोजना के तहत रिंग रोड पर पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच कारिडोर विकसित कर 2.7 किलोमीटर भाग को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसमें सड़क के करीब 1.5 किलोमीटर भाग को एलिवेटेड बनाया जाएगा। इस योजना पर करीब 200 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। रिंग रोड पर पंजाबी बाग से राजा गार्डन के बीच तीन जगह जाम लगता है। यहां मोती नगर में पहले से 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर बना है, जो सिंगल फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर से पंजाबी बाग से राजा गार्डन की ओर जा सकते हैं, मगर राजा गार्डन से पंजाबी बाग जाने के लिए फ्लाईओवर नहीं है। इसके चलते रिंग रोड के इस भाग में अक्सर व्यस्त समय में जाम लगा रहता है। अब इसे डबल किया जाएगा। इसी मार्ग पर आगे चलने पर क्लब रोड लालबत्ती पर फ्लाईओवर पहले से ही बना है। यह फ्लाइओवर भी सिंगल है। इसका इस्तेमाल राजा गार्डन से पंजाबी बाग जाने के लिए किया जाता है। लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस फ्लाईओवर को डबल किया जाएगा। इसके अलावा इस फ्लाईओवर को करीब 600 मीटर आगे बढ़ाया जाएगा।

विमान यात्रियों की होगी कोरोना जांच

संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटाइन किया गया अनिवार्य

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब देश के अलग अलग शहरों से आने वाले विमानों में सवार यात्रियों की कोविड जांच की जाएगी। हालांकि अभी सभी यात्रियों के बजाय कुछ ही यात्रियों की जांच की जाएगी। यदि जांच के नतीजे संक्रमण पाया जाएगा तो यात्री के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर कोविड जांच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए किए गए इंतजामों को लेकर सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया गया है। ऐसे यात्री जो मास्क के इस्तेमाल ढिलाई बरतते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ थाने में भी शिकायत की जाएगी। डायल का कहना है कि यह प्रशासन द्वारा लिया गया फैसला है। बता दें कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन कोरोना को लेकर बिगड़ रहे हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले चार दिनों में दिल्ली में 596 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। शुक्रवार को प्रशासन की तरफ से जारी रिपोर्ट में 1307 कंटेनमेंट जोन थे जो मंगलवार को बढ़कर 1903 हो गए। जबकि 23 मार्च को यह संख्या 976 थी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक कुल 17046 कंटेनमेंट जोन बने है। इनमें से 15701 को डी-कंटेन कर दिया गया है। 21 जून के बाद अब तक 16022 कंटेनमेंट जोन बने हैं। अब दिल्ली में सबसे ज्यादा दक्षिणी जिला में 534 कंटेनमेंट हो गए हैं। जबकि 20 मार्च को इस जिला में यह संख्या 117 थी। यानी कि 10 दिन में 400 से अधिक कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। वहीं सबसे कम अब मध्य जिला में इनकी संख्या है। यहां अब इनकी संख्या 35 है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे कम संख्या रहती रही है। अब इस जिले में इनकी संख्या 45 है। जबकि 20 मार्च को इस जिले में यह संख्या 5 थी। अब कंटेनमेंट के मामले में दूसरे स्थान पर उत्ती जिला है। यहां इनकी संख्या 259 और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली जिला है। यहां इनकी संख्या 225 है। कंटेनमेंट जोन की अब लगातार बढ़ रही संख्या लोगों को डरा जरूर रही है। मगर तमाम लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

जो मास्क के इस्तेमाल ढिलाई बरतते पाए जाएंगे उनके खिलाफ थाने में भी शिकायत की जाएगी।

संपादकीय

काश! वैसे घर न लौटते लोग

इन दिनों हम दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन की पहली बरसी मना रहे हैं। यह देशव्यापी तालाबंदी अलहदा थी, क्योंकि महज चार घंटे की सूचना पर इसे लागू किया गया था। देश भर में फंसे करोड़ों लोगों, यात्रियों, छात्र-छात्राओं और प्रवासियों की सुध नहीं ली गई थी। आज भी, लॉकडाउन की जो पहली छवि हमारी आंखों के सामने आती है, वह बेबस मजदूरों की ही है, जो पैदल अपने-अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। फिर चाहे वे पुरुष हों, महिला या बच्चे, जिसे जो भी साधन मिला, उसी से वह विदा हो गया। इस घर वापसी में कई लोग तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। यह निश्चय ही देश का सबसे बड़ा शहरी पलायन था। यह कुछ ऐसा था, जिसके बारे में न तो नीति-नियंता अनुमान लगा सके थे, और न ही आम जनता। लॉकडाउन और इसकी वजह से हुए शहरी पलायन ने सभी प्रवासियों को समान रूप से प्रभावित नहीं किया। इसने उन लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाई, जो देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सबसे निचले दर्जे पर हैं। इनकी कमाई कम है और रोजगार अनिश्चित, इसलिए जीवित रहने के लिए ये कभी ग्रामीण, तो कभी शहरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते रहते हैं। इनमें भी सबसे अनिश्चित जीवन मौसमी प्रवासियों का होता है, जो अन्य राज्यों में निर्माण-कार्यों, ईंट भट्ठों, खदानों आदि में काम करने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब इन प्रवासी कामगारों की नौकरी खत्म हो गई, कार्यस्थल पर तैनात मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ठेकेदारों ने मजदूरी देने से इनकार कर दिया, और किराये पर रहने वाले कामगार मकान-मालिक का किराया चुकाने के लिए चिंतित हो उठे। ऊपर से वायरस के खौफ ने उनकी असुरक्षा और बढ़ा दी। ये सब उनके पलायन का कारण बने। जनगणना और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर मेरा यही अनुमान है कि ऐसे गरीब श्रमिकों की संख्या लगभग 13 करोड़ थी, जिनमें से 5.5 करोड़ दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, जबकि तीन करोड़ अंतर-राज्यीय मौसमी प्रवासी थे। सरकार का मानना है कि लगभग 1.1 करोड़ प्रवासी घर लौटे, जो सटीक नहीं जान पड़ता है, क्योंकि कई बार पैदल चलकर या स्वयं के साधन से मजदूर गृह राज्य को लौटे थे। शुरुआत में सरकारों और सार्वजनिक परिवहन तंत्र में समन्वय का अभाव दिखा, जबकि महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों का प्रबंधन ये बखूबी कर लेते हैं। यहां तक कि इन मजदूरों के यात्रा भाड़े का भुगतान कौन करेगा, इसका जवाब भी नहीं था। मगर, बाद में केंद्र सरकार ने जन-वितरण प्रणाली और मनरेगा का विस्तार किया, और कुछ संवेदनशील राज्य सरकारों ने खास कदम भी उठाए, जिससे गरीब प्रवासियों व उनके परिवारों को कुछ राहत मिल सकी।

प्रवासी संकट सामने आने के बाद पहली बार नीति-निर्माताओं के साथ-साथ शहरी और औद्योगिक भारत को यह एहसास हुआ कि सहायक सेवाओं और विकास में इन मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी अनुपस्थिति से श्रम-बल में भारी अंतर आया। ऐसे में, संवेदनशील नागरिकों का यह तर्क वाजिब था कि प्रवासी श्रमिक केवल सस्ते श्रम और सेवाएं देने के माध्यम नहीं हैं, बल्कि उन्हें भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, उनके काम को पूरा महत्व मिलना चाहिए और आवास, बुनियादी सुविधाएं व स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए।

अब एक साल के बाद यह देखने का समय है कि इस सबक पर सभी भागीदार पक्षों ने गौर किया अथवा नहीं? चूंकि शहरी और औद्योगिक विकास की प्रक्रियाओं में प्रवासी मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से वापस लौटने लगे हैं, तो क्या अब उनका कामकाजी जीवन अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और महफूज रहेगा? इन प्रश्नों के जवाब अब तक मिले-जुले रहे हैं। जब मजदूरों की कमी थी, तब कंपनियों ने प्रवासियों के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाए और उन्हें प्लेन तक से वापस बुलाया। लेकिन जैसे-जैसे उनकी आवक बढ़ती गई, नौकरी की अनिश्चितता और कम आय मजदूरों पर भारी पड़ने लगी है। नियोक्ताओं के साथ न तो रोजगार की शर्तों में सुधार हुआ, और न ही मजदूरी में। आलम यह है कि उद्योग जगत संक्रमण के दूसरे चरण का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं दिख रहा। एक बार फिर केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कानूनी व सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। हाल के श्रम कानूनों में, संगठित क्षेत्र में अंतरराज्यीय मजदूरों को भी पंजीकृत करने और निर्माण-कार्यों में लगे प्रवासी श्रमिकों को संगठित क्षेत्र का लाभ देने के प्रावधान किए गए हैं। एक स्पष्ट समझ बनी है कि प्रवासी श्रमिकों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता और नीतिगत लाभ उन्हें मुहैया कराने ही होंगे। सबसे आशाजनक पहल तो नीति आयोग ने की है। वह संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और नागरिक संगठनों को शामिल करके प्रवासी मजदूरों के लिए एक नीतिगत मसौदा तैयार कर रहा है। अगर इसको स्वीकृति मिल जाती है, तो उपेक्षित मजदूरों के इस विशाल समूह के लिए देश की यह पहली नीति होगी। इसमें प्रवासियों की गरिमा को मान्यता दी गई है और कामगार व मनुष्य के रूप में उनके अधिकारों के सम्मान की वकालत की गई है। उम्मीद की यह किरण निस्संदेह प्रवासी संकट के सबसे स्याह दौर में उभरी है, मगर अब भी कई बुनियादी मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा हर मानव का अधिकार है और मूल निवास-स्थान में भेदभाव किए बिना न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा हर प्रवासी श्रमिक को मिलनी चाहिए। प्रवासी कामगारों को जो चिंता सबसे अधिक खाए जा रही है, वह है रोजगार की अनिश्चितता। श्रम कानूनों में हालिया बदलावों ने ठेकेदार आधारित रोजगार और पूर्णत- अस्थाई नौकरी का विस्तार करके इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। फिर, प्रवासी बनने की मूल वजह गहरा क्षेत्रीय असंतुलन है, जिस पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया है। लिहाजा, लॉकडाउन के इस एक वर्ष के बाद प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है। प्रवासी व गैर-प्रवासियों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए हमें अब भी बहुत कुछ करना है।

प्रवीण कुमार सिंह

एक धार्मिक ग्रंथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

मुस्लिम समाज द्वारा यह स्वीकार कर लेना वही बड़ा कार्य होगा, जो अपनी पवित्र पुस्तकों के बारे में यहूदी, ईसाई लोग पहले कर चुके हैं। इस पर अमेरिकी बिशप और हार्वर्ड में व्याख्याता रहे जॉन शेल्बी स्पॉन्ग ने 'द सिंस ऑफ स्क्रिप्चर' (पवित्र पुस्तक के पाप) नामक पुस्तक ही लिखी है। उन्होंने विश्लेषण किया कि बाइबल विशेषकर ओल्ड टेस्टामेंट में कई बातें हिंसात्मक हैं। यदि मुस्लिम भी ऐसी ही कोई पहल करें तो यह एक बड़ा रचनात्मक कदम होगा। इससे दुनिया समझेगी कि मुसलमान भी विवेकपूर्ण ढंग से सोच-विचार कर सकते हैं। इससे उनका दूसरे समुदायों के साथ विश्वास का पुल बनना शुरू हो सकेगा।

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दी गई याचिका चर्चा में है। इसमें कुरान से 26 आयतें हटाने का निवेदन है। रिजवी के अनुसार इनका इस्तेमाल 'आतंकवाद, हिंसा और जिहाद फैलाने में होता है।' रिजवी के अनुसार, प्रोफेट मुहम्मद की मृत्यु के बाद पहले तीन खलीफा ने कुरान संकलित करने में कई आयतें जोड़ दीं, ताकि उन्हें 'युद्ध द्वारा इस्लाम के विस्तार में सहूलियत हो।' यह चिंता पहली बार या भारत में ही नहीं है। गत वर्षों में तुर्की, सऊदी अरब और इराक में भी कुरान को लेकर संशोधन-सुधार की मांगें उठी थीं। तुर्की के अधिकारियों को सूचना मिली कि सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र कुरान पढ़कर इस्लाम से उदासीन होने लगते हैं। सऊदी अरब में सुझाव आया कि कुरान की कुछ बातों की जांच-परख कर समयानुकूल संशोधन किया जाए।

सऊदी लेखक अहमद हाशिम के अनुसार प्रचलित कुरान खलीफा उस्मान द्वारा तैयार कराए जाने के कारण उसके निर्माण में 'मानवीय हस्तक्षेप' हो चुका है, अत- उसे अपरिवर्तनीय मानना अनुपयुक्त है। यह भी तथ्य है कि कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रिया में कुरान का सार्वजनिक रूप से वितरण प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्विट्जरलैंड के सुरक्षा विभाग ने भी यही अनुशंसा की थी। चीन में मुसलमानों को कुरान से विमुख करने की कोशिश होती है। रूस की एक अदालत ने कुरान के एक विशेष अनुवाद को प्रतिबंधित किया था। अनेक जाने-माने मुस्लिम लेखक-लेखिकाओं ने भी वैसी चिंता जताई है, जैसी रिजवी ने प्रकट की है। यही काम अतीत में यूरोपीय नेताओं और विद्वानों द्वारा भी किया जा चुका है।

वसीम रिजवी की दलील है कि 26 आयतों के सहारे ही जिहादी लोग मुस्लिम युवाओं को आतंकी बनाते हैं, जिससे दुनिया भर में लाखों-लाख निर्दोषों की हत्याएं होती रही हैं। ये ऐसी बातें नहीं, जिनका परीक्षण नहीं हो सकता। 9/11 के दौरान न्यूयॉर्क में तबाही मचाने वाले मुहम्मद अट्टा ने बाकायदा लिखा था कि 'हमारे लिए यही काफी है कि कुरान की आयतें अल्लाह के शब्द हैं।' अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने सऊदी शासक किंग फहद को एक पत्र लिखकर कहा था कि 'सारा झगड़ा ही इस्लाम के अनुसार चलने या न चलने पर' है। इस पत्र में कुरान की आयतें उद्धृत करके कहा गया था कि इस्लाम से हटने पर 'हम अल्लाह के मजहब में विश्वास कायम करने और उन विश्वासों के लिए बदला लेंगे।'

इराक में अमेरिकी कर्मचारी निक बर्ग का कत्ल करने वालों ने भी कुरान का हवाला दिया था। यूरोप में जिहादी प्रदर्शन करने वाले कुरान की आयतों का उल्लेख करते हैं। जुलाई 2016 में बांग्लादेश में जिहादियों ने 20 विदेशियों का गला रेत कर कत्ल किया था, यह कहते हुए कि जो कुरान नहीं जानते, वे कत्ल होने लायक हैं। इस्लामिक स्टेट के झंडे पर लिखे शब्द कुरान से लिए गए हैं।

वह कुरान और सुन्ना के ही हिसाब से चलने का दावा करता है।

भारत में कुरान को लेकर दो मुकदमे चल चुके हैं। 1985 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में चांदमल चोपड़ा ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कुरान से कुछ उद्धरणों का हवाला देकर हिंसा और सामाजिक विद्वेष फैलने की शिकायत की गई थी। उस याचिका को न्यायमूर्ति बिमल चंद्र बसाक ने यह कहकर खारिज किया था कि किसी समुदाय द्वारा पवित्र मानी जाने वाली किताब पर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता। इस मुकदमे का विवरण सीताराम गोयल की पुस्तक 'कलकत्ता कुरान पिटीशन' में है। दूसरी बार, कुरान का मामला 1986 में दिल्ली में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जेड एस लोहाट की अदालत में आया। इंद्रसेन शर्मा नामक एक व्यक्ति ने कुरान की 24 आयतें उद्धृत करते हुए पोस्टर प्रकाशित किया। उसमें लिखा था कि 'ऐसी अनेक आयतें कुरान में हैं जो दुश्मनी, विद्वेष, हिंसा और घृणा आदि को बढ़ावा देती हैं। अदालत से ऐसी आयतों को हटाने की मांग की गई। इस पोस्टर के प्रकाशन के बाद दिल्ली पुलिस ने इंद्रसेन को गिरफ्तार कर लिया। दंड संहिता की धारा 153 ए और 295 ए के तहत उनकी पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने पाया कि पोस्टर वाली आयतें एक बड़े इस्लामी प्रकाशन से हू-ब-हू उद्धृत थीं। मजिस्ट्रेट ने पोस्टर लगाने को सामान्य विचार माना, जिसे व्यक्त करना अपराधिक मामला नहीं। यह फैसला 31 जुलाई 1986 को दिया गया था। नोट करने की बात है कि इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं हुई।

अब तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में कुरान पर याचिका आई है। इस बार एक मुस्लिम नेता ने इसे दायर किया है। शिकायत वही है कि कुरान की कई आयतें सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाती हैं। पिछले दोनों मामलों में न्यायाधीशों ने कुरान के प्रति सम्मान दिखाते हुए भी ऐसे आरोप खारिज करने से इन्कार किया था। बीते तीन दशकों में दुनिया भर का भरपूर व्यावहारिक अनुभव भी जुड़ गया है। अनेक मुस्लिम देशों में भी वह चिंता व्यक्त हो रही है, जो रिजवी ने जताई है। इस वैश्विक अनुभव के मद्देनजर रिजवी के आरोप की पक्की परख हो सकती है।

हालांकि प्रसिद्ध पुस्तकों को संशोधित या प्रतिबंधित करना अनुचित है। जाने-माने चिंतक रामस्वरूप के अनुसार, 'सदियों पुरानी किसी किताब को यथावत रहने का अधिकार है। जो किसी किताब से असहमत हैं, वे अपनी बात लिखें। नए नियम और प्रस्ताव दें, वह अधिक उपयुक्त होगा।' अत- पुस्तकों की खुली समालोचना होनी चाहिए, ताकि अंधविश्वास और सत्य का अंतर साफ रहे। कुरान से कुछ आयतों को हटा या संशोधित कर देना जरूरी नहीं है। केवल यह मान लिया जाए कि ऐसी चीजें उसमें हैं, जो हानिकारक संदेश देती हैं। मुस्लिम समाज द्वारा यह स्वीकार कर लेना वही बड़ा कार्य होगा, जो अपनी पवित्र पुस्तकों के बारे में यहूदी, ईसाई लोग पहले कर चुके हैं।

इस पर अमेरिकी बिशप और हार्वर्ड में व्याख्याता रहे जॉन शेल्बी स्पॉन्ग ने 'द सिंस ऑफ स्क्रिप्चर' (पवित्र पुस्तक के पाप) नामक पुस्तक ही लिखी है। उन्होंने विश्लेषण किया कि बाइबल विशेषकर ओल्ड टेस्टामेंट में कई बातें हिंसात्मक हैं। यदि मुस्लिम भी ऐसी ही कोई पहल करें तो यह एक बड़ा रचनात्मक कदम होगा।

कहीं भारी न पड़ जाए लापरवाही, कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की बढ़ाई चिंता

कोरोना की चुनौतियों से लगभग पूरा देश ही उबरकर आगे बढ़ चला था। टीकाकरण के क्रमबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन से भी जनजीवन के पटरी पर लौट आने की उम्मीद बंधी थी। स्कूल-कॉलेज भी खुलने लगे थे। धीरे-धीरे पढ़ाई भी नियमित होने लगी थी। महीनों से ठहरी पड़ी यात्रओं को भी तीव्र गति मिलने लगी थी। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या जुटने लगी थी। बाजार एवं अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने लगी थी। गांवों को गए हुए प्रवासी मजदूर शहरों में वापस लौटने लगे थे। कारोबारी-उद्यमी उन्हें ससम्मान वापस काम पर रख भी रहे थे। परंतु कोविड की दूसरी लहर और बढ़ते आंकड़ों ने एक बार पुन- भय मिश्रित चिंताओं एवं आशंकाओं को हवा दी है।

अफवाहों के बाजार को गर्म किया है। सीमित संसाधन, भिन्न भौगोलिक संरचना एवं वायुमंडल और विशाल एवं सघन आबादी के बावजूद भारत ने जिस आत्मविश्वास एवं सफलता के साथ कोविड-19 से लड़ाई लड़ी, वह अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। भारत उन चुनिंदा देशों में अग्रणी है, जिसने न केवल स्वयं इस महामारी से लड़ाई लड़ी, बल्कि दुनिया के अन्य तमाम देशों की भी मुक्तहस्त मदद की। भारत इस कोविड-काल में दुनिया का भरोसेमंद साथी बनकर उभरा। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने तो हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट करके भारत को धन्यवाद दिया। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं लोकमान्यता के प्रति भी उनका कृतज्ञता भरा आदर था।

पर कोविड की इस दूसरी लहर ने हमारी गौरवपूर्ण उपलब्धि के इस चमकीले पृष्ठ को थोड़ा धुंधला किया है। हमारी लापरवाही कहीं अपने चिकित्सकों-विज्ञानियों, सरकारी-गैर सरकारी विभागों के मुस्तैद अधिकारियों-कर्मचारियों तथा प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिक-समाज के परिश्रम पर पानी न फेर दे। उन्होंने अपने परिश्रम-पुरुषार्थ से कोविड से संघर्ष के मोर्चे पर देश को जो वैश्विक बढ़त दिलाई, हमारी लापरवाही कहीं उसे पीछे न धकेल दे। लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में आ-जा रहे हैं, चौक-चौराहे पर अकारण बैठ रहे हैं, शरीरिक दूरी और सैनेटाइजेशन का पालन नहीं कर रहे हैं। शादियों-उत्सवों, सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं त्योहारों में कोविड-19 से बचने हेतु वे पर्याप्त सावधानी एवं सतर्कता नहीं बरत रहे। हवाई-यात्र को छोड़कर यातायात के अन्य साधनों का उपयोग करते हुए भी वे सतर्कता एवं सावधानियों का ध्यान नहीं रख रहे।यह सत्य है कि टीकाकरण के पश्चात अब न तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, न ही बाजार, जनजीवन एवं अर्थव्यवस्था को ही बाधित किया जा सकता है। ऐसे फैसलों से समाज के बड़े तबके के समक्ष आजीविका का संकट तो खड़ा हो ही जाएगा। इसके साथ-साथ मूडीज-फिच जैसी वैश्विक रेटिंग संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे प्रामाणिक वैश्विक संगठनों ने वित्त वर्ष 2021-22 में देश की भावी विकास दर दहाई अंकों में रहने की जो चमकदार संभावना जताई है वह भी प्रभावित एवं धूमिल हो जाएगी। वैसे ही लॉकडाउन एवं कोविड काल बहुतों के लिए मुसीबत का सबब बना है। वे अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य एवं स्वभाव पर इसका बड़ा गहरा, व्यापक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। वृद्ध पहले से भी अधिक एकाकी हुए हैं। उनका पार्कों-क्लबों-समारोहों में आग्रहपूर्वक जाने का वर्षों पुराना अभ्यास एवं सामान्य चलन बाधित हुआ है।

बच्चों में असामाजिकता की भावना घर कर गई है। उनका सहज-स्वाभाविक बचपन दांव पर लगा है। वे या तो अकेले रहना पसंद करने लगे हैं या मोबाइल एवं गैजेट्स पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई है। यहां तक कि वे अपने घर आने-जाने वाले मेहमानों-परिचितों से भी आमने-सामने का संवाद नहीं करना चाहते। खिंचे-खिंचे, चिढ़े-कुढ़े रहना उनका स्वभाव बनता जा रहा है। चिंता, तनाव, अवसाद, मोटापा, चिड़चिड़ापन आदि इस लॉकडाउन एवं कोविड-काल के सह-उत्पाद हैं। बच्चे इन बीमारियों एवं परेशानियों के आसान एवं सर्वाधिक शिकार हैं। ऑनलाइन शिक्षा इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक विकल्प बनकर तो अवश्य उभरी, पर उसकी कुछ सीमाएं हैं। इंटरनेट ज्ञान एवं सूचनाओं के उस अथाह-अनंत सागर की तरह है जिसमें डूब जाने का खतरा अधिक है और पार उतरने की संभावना कम। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर इंटरनेट पर पड़ी अश्लील सामग्रियों का दुरुपयोग इन दिनों आम चलन है। क्या यह सत्य नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा स्कूल में होने वाले सामाजीकरण एवं समग्र विकास का माध्यम नहीं बन सकती? वैसे भी शिक्षा केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं, व्यक्तित्व का रूपांतरण है।

इसलिए स्वयं समेत अपने बच्चों, बुजुर्गों, परिजनों, पास-पड़ोस के स्वास्थ्य एवं भविष्य को बचाने के लिए हमें आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, बताए गए नियमों-निर्देशों का अक्षरश- पालन करना चाहिए। कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देशों एवं सावधानियों को दैनिक जीवनचर्या का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। यह हमारी महती आवश्यकता भी है और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी।

अमीरी बनाम खुशहाली

पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से देश के 34 शहरों में कराए गए एक सर्वे की रिपोर्ट में लुधियाना, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को भारत के सबसे खुश शहरों का तमगा हासिल हुआ है। लोगों की खुशी का स्तर नापने के लिए इस अध्ययन में पांच प्रमुख कारक रखे गए थे- कामकाज, रिश्ते, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, लोकोपकार और धर्म-अध्यात्म। दुनिया के स्तर पर भी हैपिनेस इंडेक्स जारी किए जाने की खबरें हर साल आती रहती हैं। इन सूचनाओं से हमें अलग-जगहों पर लोगों की मनोदशा को लेकर कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इनसे धन के अलावा खुशहाली के कुछ दूसरे कारक भी नीति निर्माताओं के अजेंडे पर आते हैं। दुनिया में विकास के जो पैमाने स्थापित हैं और जिन पर खुद को कामयाब दिखाने के लिए जीडीपी के आंकड़े लगातार बढ़ाने की कोशिश प्राय- सभी सरकारें करती हैं, उनकी आम लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में कितनी भूमिका है, कुछ तार्किक बातचीत इस बारे में भी होती चलती है।दुनिया में भूटान वह अकेला देश है जहां सरकार बाकायदा जीएनएच इंडेक्स को आधार बनाकर अपनी नीतियां तय करती है और लोगों के जीवन में खुशी लाना अपना लक्ष्य मानती है।

वहां 2008 में लागू हुए संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। यहां गौर करने की बात यह है कि भौतिक सुविधाओं तक पहुंच एक ठोस हकीकत है जिसे देखा, समझा और नापा जा सकता है। उन सुविधाओं की बदौलत किसको कितनी खुशी मिलती है या नहीं मिलती, यह व्यक्ति की अपनी बनावट और मनःस्थिति पर निर्भर करता है। इसे कैसे नापा जाए और सरकारें इसे नीति निर्धारण का आधार बनाएं तो उन नीतियों की सफलता-असफलता का आकलन कैसे हो? हालांकि यह व्यक्ति के मनोजगत की बात है, फिर भी इसके कुछ सूत्र पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टडी में मिलते हैं। जैसे, रिश्तों के फैक्टर को लें तो रिपोर्ट में पाया गया कि शादीशुदा लोगों के मुकाबले अविवाहित लोग खुद को ज्यादा खुश बताते हैं। इसका मतलब यह लगाया गया कि स्थिरता के बजाय जिम्मेदारियों के झंझट से बचे रहना खुशी का एक जरिया हो सकता है।

सवाल यह है कि आखिर वे कौन सी जरूरतें या जिम्मेदारियां हैं जिनसे किसी को अपने जीवन की खुशी छिनती हुई जान पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई की चिंता जैसी खुचड़ सरकार की नीतियों में मामूली हेरफेर से कम की जा सकती है। ऐसे ही बीमार पड़ने पर किसी आर्थिक संकट में फंसे बगैर इलाज हो जाने का भरोसा महत्वपूर्ण है और एक सही सरकारी नीति इस भरोसे को पुख्ता बना सकती है।

बहरहाल, इस अध्ययन से इतना तो पता चलता ही है कि सरकारी नीतियों की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता के सवाल को पर कैपिटा इनकम के आंकड़े से निपटाने के बजाय उनके सुकून को अपनी सफलता की कसौटी बनाए।

संघर्ष की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले कम्युनिस्टों को सता रहा अस्तित्व का डर

माले राजद को अपना दुश्मन नंबर एक कहता था, मगर 2020 के विधानसभा चुनाव में भाकपा, माकपा के साथ ही माले ने भी राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़ा। माले 12 सीटें जीतने में सफल रहा, जो उसका अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या माकपा बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के सहारे अपनी डूबती नैया को पार लगा पाएगी? दूसरा सवाल यह है कि जैसे भाकपा कांग्रेस की पिछलग्गू होकर उसकी मोहताज पार्टी बनकर रह गई है, क्या कुछ वैसी ही नियति माकपा की भी होने जा रही है।

वर्ष 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और उससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी माकपा के रूप में एक नया दल निकला। दल विभाजन के बाद 1971 में हुए पांचवीं लोकसभा के चुनाव तक माकपा और भाकपा कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर रहे थे। 'निजी पूंजी की समाप्ति और उत्पादन के आर्थिक संसाधनों का समाजीकरण, जो जमीन को जोते-बोये, वही जमीन का मालिक होये' जैसे तमाम लोकलुभावन नारों के साथ विदेश से आयातित साम्यवाद और समाजवाद का भारत में प्रवेश और उनका भारतीय जनमानस पर प्रभाव अपने आप में शोध का विषय है, फिर भी एक बात अवश्य है कि दोनों ही दलों ने भारत में क्लास (वर्ग) के बदले कास्ट (जाति) का ही सहारा लेकर अपना विस्तार किया। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बड़े-बड़े समाजवादी नेता पहले जातिवादी हुए और अंत में परिवारवादी राजनीति के पर्याय बन गए। साम्यवादियों और समाजवादियों में एक और समानता है और वह है उनका विभाजन।

देश के जिन पांच राज्यों में फिलहाल विधानसभा चुनाव प्रक्रिया जारी है उनमें से दो राज्य बंगाल और केरल में वामपंथी न केवल कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरे, बल्कि दशकों तक सत्ता में कायम रहे। इस बार के चुनावों में स्थिति कुछ अलग है। केरल में जहां कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीत तल्ख लड़ाई जारी है, वहीं बंगाल में उनकी चुनावी साझेदारी है। यह साझेदारी समझदारी की है या लाचारी की, इस बारे में चुनाव परिणामों के बाद ही

कुछ कहना उचित होगा। बंगाल में कांग्रेस के साथ मुस्लिम संगठन 'इंडियन सेक्युलर फ्रंट' को गठबंधन में शामिल करना यह दर्शाता है कि अब शायद कम्युनिस्टों को अपनी पहचान खत्म होने का संकट दिख रहा है। एक वक्त वह भी था जब महंगाई, बेरोजगारी और शोषण के खिलाफ लाल झंडे के बैनर तले गरीबों को लामबंद करने में कम्युनिस्ट न केवल सफल हो रहे थे, बल्कि राजनीति में अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे थे। उनके क्रियाकलाप उन्हें अलग पहचान दिलाते थे। दूसरे दल से आने वाले दलबदलू, पैसे वाले, घोर जातिवादी और भ्रष्टाचारी कम्युनिस्ट पार्टी का टिकट पाने में सफल नहीं होते थे। उनके लिए विचारधारा और संगठन से ऊपर कोई नहीं था। अन्य दलों की तरह पार्टी के झंडे पर किसी नेता का फोटो नहीं होता था। व्यक्ति से बड़े दल के कथन को कम्युनिस्टों ने साकार भी किया। ज्योति बसु का प्रधानमंत्री नहीं बनना और सोमनाथ चटर्जी को टिकट से वंचित करना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जनसमस्याओं को लेकर संसद से सड़क तक संघर्ष करने वाले कम्युनिस्टों को अगर अपनी पहचान का संकट सता रहा है तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय विषयों पर उनकी प्रतिबद्धता और विदेशी चश्मे से भारत को देखने के कारण वे जनता और जमीन से कटते चले गए। 1974 में जेपी आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। सोवियत रूस समर्थक भाकपा ने तब उस आंदोलन का विरोध करने के साथ ही जेपी को अमेरिकी एजेंट तक करार दिया था। आपातकाल में वाम नेता फासिस्ट विरोधी सम्मेलन कर रहे थे। 1977 के चुनाव नतीजे और तदोपरांत चुनावी आंकड़े दर्शाते हैं कि भाकपा उसके बाद से अपनी पहचान के लिए जूझती आई है। वहीं माकपा और कांग्रेस के संबंधों से पर्दा तब उठ गया, जब 1980 में इंदिरा गांधी ने दोबारा सत्ता में लौटने के बाद कई राज्यों की सरकारों को तो बर्खास्त कर दिया, लेकिन माकपा के नेतृत्व वाली बंगाल और केरल सरकार को नहीं छेड़ा। बंगाल और केरल माकपा के अभेद्य किले माने जाते थे, लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का समर्थन कर माकपा ने अपने गढ़ में खुद ही सेंध लगवा दी। 2004 में माकपा के 43 लोकसभा प्रत्याशी जीते थे जो 2009 में घटकर 16 और 2014 में नौ रह गए। इन नौ में से पांच तो केरल से ही थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में तो कम्युनिस्टों का खाता ही नहीं खुला और उनकी विदाई हो गई। जैसे बंगाल, केरल और त्रिपुरा दशकों तक माकपा के गढ़ रहे, वैसे ही बिहार में वर्षों तक भाकपा का प्रभाव रहा, जो धीरे-धीरे निष्प्रभावी होता गया। 1991 में बिहार की आठ लोकसभा सीटों पर जीतने वाली पार्टी 1998 से लेकर 2019 तक राज्य में एक अदद सीट तक नहीं जीत पाई।

कम्युनिस्ट जब टूटकर अलग होते हैं तो एक दूसरे पर संशोधनवादी होने का आरोप लगाते हैं। माकपा ने भाकपा पर तो माकपा से टूटकर बने भाकपा-माले ने माकपा पर संशोधनवादी होने का आरोप लगाया था। माले का बिहार में अपना एक आधार था, परंतु 2010 के विधानसभा चुनाव में यह दल भी शून्य पर सिमट गया। बाध्य होकर 2015 में तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े। फिर भी केवल माले तीन सीट जीत पाया। वर्ष 1997 में सिवान में माले से जुड़े जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या सांसद शहाबुद्दीन ने कराई, जो लालू प्रसाद के करीबी रहे। माले राजद को अपना दुश्मन नंबर एक कहता था, मगर 2020 के विधानसभा चुनाव में भाकपा, माकपा के साथ ही माले ने भी राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़ा। माले 12 सीटें जीतने में सफल रहा, जो उसका अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है।

आज बड़ा सवाल यही है कि क्या माकपा बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के सहारे अपनी डूबती नैया को पार लगा पाएगी? दूसरा सवाल यह है कि जैसे भाकपा कांग्रेस की पिछलग्गू होकर उसकी मोहताज पार्टी बनकर रह गई है, क्या कुछ वैसी ही नियति माकपा की भी होने जा रही है। क्या वामपंथी अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं? बंगाल में कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठबंधन के परिणाम इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने केस वापस लेने का दिया आदेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2004 में पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के आदेश दिया है। मुकदमा वापसी के आदेश की कॉपी मंगलवार को शैलेंद्र सिंह को मिली, तो उन्होंने इंटरनेट मीडिया के जरिये यूपी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ न्यायालय के आदेश की कॉपी अपलोड कर बताया है कि उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस ले लिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लिया है। वाराणसी के सीजेएम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद शैलेंद्र सिंह ने योगी सरकार को धन्यवाद कहा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में लिखा है, 2004 में जब मैंने माफिया मुख्तार अंसारी पर एलएमजी केस में पोटा लगा दिया था, तो मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया, जिसे न मानने के फलस्वरूप मुझे डिप्टी एसपी पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर, राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर वाराणसी में आपराधिक मुकदमा लिखा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार बनी तो, उक्त मुकदमे को प्राथमिकता के साथ वापस लेने का आदेश पारित किया गया, जिसे माननीय सीजेएम न्यायालय द्वारा 6 मार्च, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायालय के आदेश की नकल आज ही प्राप्त हुई। मैं और मेरा परिवार योगी जी की इस सहृदयता का आजीवन ऋणी रहेगा। संघर्ष के दौरान मेरा साथ देने वाले सभी शुभेक्षुओं का, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

बता दें कि जनवरी, 2004 में यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने का राजफाश किया था।

उन्होंने एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध पोटा भी लगाया था। इस पर तत्कालीन सरकार में हंगामा मच गया और शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इस पर व्यथित होकर शैलेंद्र सिंह ने यूपी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के इस्तीफा देने के कुछ महीने बाद वाराणसी के कैंट थाने में डीएम कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लालजी की तरफ से तोड़फोड़ मारपीट हंगामा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और पुलिस ने चार्जशीट तक कोर्ट में दाखिल कर दी। अब शैलेंद्र सिंह पर दर्ज इस केस को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश जारी किया है।

महिला के लिए रिजर्व हुई पंचायत सीट तो संकल्प तोड़ बिना शुभ मुहूर्त रचाई शादी

बलिया । उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद से कई रोचक किस्से भी सामने आने लगे हैं। इस चुनाव में आरक्षण ने कई दिग्गज प्रत्याशियों को चुनाव से पहले ही पटखनी दे दी है। बहुतों की लंबे समय की समाजसेवा भी व्यर्थ गई, लेकिन बलिया के विकासखंड मुरलीछपरा के ग्राम पंचायत शिवपुर कर्ण छपरा एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको आरक्षण भी मात नहीं दे पाया। लगभग एक दशक तक समाज सेवा करने के बाद ग्राम प्रधान बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 45 वर्षीय हाथी सिंह ने अपनी पंचायत सीट महिला के लिए आरक्षित घोषित हो जाने के बाद शादी कर ली।

बलिया जिले के करन छपरा गांव के निवासी हाथी सिंह ने वर्ष 2015 में प्रधानी चुनाव लड़ा और वह उपविजेता रहे। हाथी सिंह जिस सीट से इस बार जीत की उम्मीद लगाए थे, वह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित कर दी गई है। इस कारण उनके निर्वाचित होने की उम्मीद भी टूट गई। इस पर उनके समर्थकों ने सुझाव दिया कि वह शादी कर लें तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं।

हाथी सिंह ने इस सुझाव पर अमल करते हुए आखिरकार 26 मार्च को गांव के धर्मनाथजी मंदिर में शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाह को खर-मास के दौरान किया गया, जो हिंदू परंपराओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को नामांकन से पहले शादी करनी थी। इसलिए आननफानन शादी का आयोजन किया गया। उनकी दुल्हन अभी स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही है और अब ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।

26 मार्च को शादी रचाने के बाद अब शवपुर कर्ण छपरा पंचायत में चुनावी मैदान पूरी तरह सज चुका है। हाथी सिंह ने कहा कि वह पिछले पांच सालों से प्रधानी चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके समर्थक भी प्रचार में पूरी तरह जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी शादी नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन मेरे समर्थकों के कारण वह फैसला बदलना पड़ा। मेरी मां 80 साल की हैं और वह चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। इस कारण भी शादी करने का फैसला लिया। अब निर्णय समाज के हाथ में है।

संक्षिप्त खबर

यूपी के बाराबंकी में ननिहाल आए बालक की नृशंस हत्या, जीभ काटकर फंदे से लटकाया; पास पड़ा मिला नींबू और...

बाराबंकी । होली मनाने नाना के घर आये दस वर्षीय बालक की नृशंस हत्या कर शव फंदे से लटका दिया गया। होली के दूसरे दिन शाम से बालक संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। घर से करीब 700 मीटर दूर जंगल में बालक का शव पाया गया। डाग स्क्वाड घटनास्थल से करीब सौ मीटर दूर पहुंचा, जहां बालक की कटी जीभ, शराब की शीशी, चाकू, नींबू और पूजन सामग्री मिली, जो हत्या के पीछे तंत्रमंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। मुंह व गुप्तांग पर नुकीले हथियार से वार- मामला लानोकटरा के शिवनाम गांव का है। यहां के रहने वाले रामजस वर्मा की पुत्री आरती कोठी का विवाह मिर्जापुर गढ़ी में रहने वाले अरविंद वर्मा से हुआ है। होली मनाने के लिए आरती 26 मार्च को पुत्र दिव्यांश (10) के साथ पिता के घर शिवनाम आई थी। 30 मार्च की शाम दिव्यांश संदिग्ध हालात में गायब हो गया था। तलाश के दौरान बुधवार सुबह परिवारजन को दिव्यांश का शव घर से करीब 700 मीटर दूर स्थित योगिनी तालाब के पूर्वी किनारे स्थित जंगल में एक पेड़ पर बेलाओं के फंदे से लटका मिला। चंद कदम की दूरी पर किशोर की साइकिल खड़ी मिली। मृतक के चेहरे, मुंह व गुप्तांग पर नुकीले हथियार से वार किया गया था और उसकी जीभ कटी हुई थी। तांत्रिक गतिविधियों सहित कई पहलुओं पर जांच- एएसपी मनोज पांडेय, सीओ नवीन सिंह भी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद मौके से बरामद शराब की शीशी, नींबू, चाकू व कटी जीभ आदि पुलिस ने कब्जे में लिया है। मृतक के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है, लेकिन पुलिस दरिंदे का सुराग नहीं लगा सकी है। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि हत्या से जुड़ी तांत्रिक गतिविधियों सहित कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्थिति और स्पष्ट होगी।

यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार चयन के लिए तय की गाइडलाइन, पार्टी पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर लगाई यह शर्त..

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष या महामंत्री चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। जिला पंचायत के सदस्य पदों पर फोकस करते हुए मैदान में उतरी भाजपा ने जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जिलों में बैठकों का सिलसिला शुरू है। जिलों से आने वाली संभावित उम्मीदवारों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय में छंटनी कर प्रदेश मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां से 3051 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में पार्टी की प्राथमिकता अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने की है। इसलिए क्षेत्रीय व जिला संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों, जैसे अध्यक्ष व महामंत्री को टिकट न देकर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए नियुक्त किए संयोजक व सहसंयोजकों पर भी यह शर्त लागू होगी। विधायकों व सांसदों से भी कहा गया है कि अपने स्वजन को चुनाव लड़वाने की बजाए आम कार्यकर्ताओं को मौका दें। इससे स्थानीय स्तर पर सक्षम कार्यकर्ताओं की टीम तैयार होगी और संगठन को ताकत भी मिलेगी।

सामाजिक संतुलन का रखेंगे ध्यान - प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय स्तर पर सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। टिकट वितरण में प्रत्याशी की छवि, समर्पण और क्षमता का आकलन करने के साथ सभी वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अन्य पिछड़ों के साथ युवाओं व महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष व पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने बताया कि प्रत्याशियों का चयन चरणवार किया जाएगा।

नामांकन में होगा शक्ति प्रदर्शन : जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों का नामांकन कराते समय समर्थकों की भीड़ जुटाई जाएगी। सभी स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों को नामांकन कराने के समय अपने जिलों में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए है। नामांकन कराते समय मंत्री व सांसद भी उपस्थित रहेंगे।

कांग्रेसी नेता की हत्या पर वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी आहत, स्वजनों को ढांढस बंधाया, कहा- एक करोड़ रुपये मुआवजा दे सरकार

प्रयागराज । प्रयागराज जिले में बेखौफ बदमाशों ने देर रात सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। झूंसी के कनिहार गांव में यूथ कांग्रेस के फूलपुर लोकसभा इकाई के उपाध्यक्ष रहे मोहम्मद अकरम (30) को गोलियों से भून दिया गया। वारदात तब हुई जब अकरम रात 11 बजे के ही करीब गांव में ही मस्जिद के पास स्थित दुकान पर जा रहे थे। बुधवार को कांग्रेस नेता अकरम के पोस्टमार्टम के दौरान स्वरूपरानी अस्पताल पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य प्रमोद तिवारी ने मृतक के पिता रफीक और छोटे भाई गुलज़ार से मिलकर अकरम की हत्या पर दुख प्रकट किया। पोस्टमार्टम के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल (एसआरएन) में अकरम के परिवार वालों के समक्ष हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की लच्चर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण नहीं है। कहा कि यूपी में रामराज नहीं जंगलराज है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने सरकार से पीड़ित के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि अकरम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उनकी हत्या पर पूरी कांग्रेस पार्टी दुखी है और ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान सुरेश यादव, नफीस अनवर, मुकुंद तिवारी, हसीब अहमद, अनिल पांडेय, जीशान अहमद, जावेद उर्फी, दीपचंद्र शर्मा, महेश त्रिपाठी, सिब्बतैन बब्लू, निजामुद्दीन, जितेंद्र तिवारी, मोहम्मद हसीन, शकील अहमद समेत आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तीन नक्सलियों को एसटीएफ ने जहानाबाद व दानापुर से दबोचा, राइफल समेत कई विस्फोटक बरामद

पटना । स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को जहानाबाद और दानापुर में छापेमारी कर तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से राइफल के साथ भारी संख्या में डेटोनेटर, पुलिस कमांडो की वर्दी, हैंड ग्रैनेड पार्ट, राइफल बोल्ट समेत कई प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा अद्धनिर्मित ग्रैनेड और रॉकेट लांचर बनाने का नक्शा भी बरामद किया गया है। एसटीएफ की विशेष टीम ने जहानाबाद जिले के करौना ओपी अंतर्गत बिस्तौल में छापेमारी कर करौना के नक्सली परशुराम सिंह और दानापुर के रामजीचक निवासी संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी टीम ने दानापुर के गजाधर चक में छापेमारी कर करौना बिस्तौल के नक्सली गौतम सिंह को गिरफ्तार किया है।

एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आग्नेयास्त्र और विस्फोटक बिहार एवं झारखंड के नक्सलियों को आपूर्ति की जाती थी। पकड़े गए नक्सली कुख्यात नक्सली लीडर अरविंद सिंह उर्फ देव कुमार सिंह के सहयोगी रहे हैं। पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है।

मालूम हो कि हाल के दिनों में गया और औरंगाबाद इलाके में नक्सलियों पर कार्रवाई की गई है। इस क्रम में गया के छकरबंधा जंगल में चार नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। कई नक्सली पकड़े भी गए हैं। नियमित रूप से कोबरा, एसएसबी और सीआरपीएफ के जवान जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। इस बीच भारी संख्या में हथियारों व विस्फोटकों की बरामदगी एसटीएफ की बड़ी सफलता है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की बरादगी से एक ओर नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है तो दूसरी ओर इनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की भी उम्मीद है।

राज सिन्हा ने मांगी माफी, विधायक और धनबाद पुलिस के बीच का विवाद खत्म

धनबाद । विधायक राज सिन्हा ने पुलिस को कहे अपशब्द पर पुलिस एसोसिएशन से माफी मांगी है। इसके बाद एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चाबंदी निरस्त कर दिया है। दरअसल विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड राज्य पुलिस एसोसिएशन ने विधायक पर मुकदमे की धमकी दी थी। धनबाद पुलिस लाइन में बुधवार को संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडेय ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय विधायक धनबाद के बयान का झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन कड़ी निंदा करता है। माननीय संस्कार भूल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन है कि पुलिसकर्मियों के सम्मान की रक्षा हेतु झारखंड पुलिस को सुसंगत कार्रवाई करने का आदेश दें। इसके साथ उन्होंने विधायक का वीडियो भी शेयर किया।

प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर रीट्वीट करते हुए विधायक ने लिखा कि- बोलचाल की भाषा में निकला हुआ शब्द है। जिस रूप में पश किया गया है, मेरी नीयत वैसी नहीं है। मैंने किसी को गाली नहीं दी है। फिर भी किसी को लगता है ते मैं क्षमा प्रार्थी हूं। विधायक के इस रीट्वीट पर एसोसिएशन मान गया कि उनके मुंह से निकला अपशब्द तकियाकलाम की तरह है। इसके बाद उनके खिलाफ की जाने वाली सारी कार्रवाई रद कर दी गई।

बोलचाल की भाषा में निकला हुआ शब्द- विधायक राज सिन्हा द्वारा माफी मांगने के बाद विवाद खत्म हो गया है। पुलिस ने भी विधायक को माफी दे दी है। इस मुद्दे पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडेय ने धनबाद पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया था। इसे रद कर दिया गया है।

आगरा में पति के सामने नवविवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपितों की गिरफ्तारी को सड़क पर उतरी भीड़

आगरा । आगरा कानपुर हाईवे पर झरना नाले के जंगल में कुछ युवकों ने मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत को अंजाम दिया। पति के साथ बाइक से मायके आ रही नवविवाहिता पत?नी के साथ बुलेट बाइक सवार तीन युवकों ने दुस्साहसिक घटना की। पहले पति-पत्नी से मारपीट कर दबाव बनाकर उनके संदिग्ध हालत में फोटो खींचे। इसके बाद पति के सामने ही विवाहिता से तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। महिला से लूटपाट करके आरोपित भाग गए। घटना के 24 घंटे बाद एत्मादपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें दो आरोपित नामजद हैं। आरोपित अपने घरों से फरार हैं।

एत्मादपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली अल्पसंख्यक संप्रदाय की नवविवाहिता सोमवार शाम को पति के साथ एत्माद्दौला क्षेत्र में अपने मायके जा रही थी। सोमवार शाम छह बजे हाईवे पर झरना नाले के पास पहुंचते ही एक बाइक पर सवार तीन युवक उनके सामने से आ गए। बाइक आगे लगाकर उन्होंने पति पत्नी को रोक लिया। इसके बाद युवक पति-पत्नी को झाड़ियों में खींच ले गए। वहां ले जाकर तीनों युवकों ने उनसे मारपीट की। दबाव बनाकर दोनों के कपड़े उतरवा लिए। इसके बाद अपने मोबाइल से वीडियो बनाई और फोटो खींच लिए।

इसके बाद एक युवक ने पति को गिरा लिया और उसके ऊपर बैठ गया। फिर युवकों ने विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किया। घिनौनी हरकत करने के बाद आरोपितों ने महिला से दस हजार रुपये, कान से सोने के कुंडल और गले से सोने की चेन लूट ली। आरोपित मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। महिला के मायके पहुंचने पर पति ने यूपी 112 पर काल करके मारपीट और लूटपाट की सूचना दी। उसने बदनामी के डर से सामूहिक दुष्कर्म की बात छिपा ली।इस पर एत्माद्दौला पुलिस मौके पर लेकर पहुंची। घटनास्थल एत्मादपुर क्षेत्र का बताकर पति-पत्नी को वहां भेज दिया।

मंगलवार दोपहर पीड़िता और उसका पति छलेसर पुलिस चौकी शिकायत करने पहुंचे। इसके बाद एसपी पश्चिम सत्यजीत गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे।जांच के बाद एत्मादपुर थाने में शाम को सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, गाली गलौज और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में शाहदरा निवासी गौरी राजपूत, मोनू नामजद हैं। एक अज्ञात युवक शामिल है। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

एत्मादपुर क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नवविवाहिता और उसका पति दहशत में था। हिम्मत करके वे पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत की। मगर, पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय उनसे पूछताछ में जुट गई। छह घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। कभी घटनास्थल तो कभी आरोपितों के घर ले जाया गया। मामला एडीजी राजीव कृष्ण और एसएसपी मुनिराज जी तक पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ।

मंगलवार दोपहर 12 बजे स्वजन दोनों को एत्मादपुर की छलेसर पुलिस चौकी लेकर पहुंचे थे। वहां पुलिस को पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी। मगर, पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। सीओ एत्मादपुर और इंस्पेक्टर एत्मादपुर भी पुलिस चौकी पर पहुंच गए।मुकदमा दर्ज कराने के बजाय वे भी घंटों सवाल-जवाब करते रहे। पीड़ित दंपती को पुलिस घटनास्थल पर ले गई। यहां से शाहदरा में ले जाकर पूछताछ की गई। अभी पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और उसके पति के बयानों में अंतर आ रहा है। इनसे ही शक पैदा हो रहा है।

आरोपितों की गिरफ्तारी को प्रदर्शन- इस सनसनीखेज घटना के बाद बुधवार सुबह आगरा के एत?माद्दौला थाना क्षेत्र में पीड़िता के समुदाय के लोग धर्म स्थल पर इकट्ठे हो गए। यहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने फेसबुक लाइव किया, जबकि युवा अपने हाथों में तख्तियां लिए थे। मौके पर बड़ी संख?या में पुलिस बल मौजूद है।

टीएनबी समेत अन्य लॉ कॉलेजों पर 12 अप्रैल को होगी हाइकोर्ट में सुनवाई

भागलपुर । हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद टीएनबी लॉ कॉलेज समेत सूबे के अन्य विधि महाविद्यालयों में संसाधनों की स्थिति में सुधार हो सकता है। संसाधनों के अभाव में कोर्ट ने नामांकन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सूबे के सभी लॉ कॉलेजों के निरीक्षण के बाद आदेश जारी किया है।

इसकी अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। 22 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने नामांकन रोकने का फैसला सुनाया था। शिक्षकों और कर्मियों की कमी से जूझ रहे लॉ कॉलेजों की स्थिति को लेकर कोर्ट ने इस मामले में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन और स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाने को कहा है। दोनों कमीशन के माध्यम से ही कर्मियों और शिक्षकों की बहालियां होनी है।

दरअसल, सूबे के किसी भी विश्वविद्यालय में कर्मियों की नियुक्ति का जिम्मा सरकार ने लिया है। राज्य शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को कर्मिचारियों की नियुक्ति करने पर रोक लगा दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि ये नियुक्तियां सरकार स्तर से ही होगी। ऐसे में अब तक मामला ठंडे बस्ते हैं।

हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सूबे के सभी लॉ कॉलेजों की जांच कराई गई थी। टीम लॉ कॉलेज भी पहुंची थी। जहां संसाधन के अभाव पर टीम के लोगों ने टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि इतने कम संसाधनों में मान्यता कैसे दी जा सकती है। इसी प्रकार सूबे के अन्य लॉ कॉलेजों में भी टीम ने निरीक्षण किया। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट टीम लेकर गए।

ऐसे में रिपोर्ट देखने के बाद हाई कोर्ट ने भी संसाधन को लेकर टिप्पणी करते हुए नामांकन पर रोक लगा दी है। अब 12 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है कि कोर्ट लॉ कॉलेज में नामांकन को लेकर क्या निर्णय देती है। तभी आगे की प्रक्रिया कॉलेजों द्वारा शुरू की जाएगी।

यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ने फिर भेजा रोपड़ जेल, 12 अप्रैल को अगली पेशी

मोहाली । यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को बुधवार दोपहर सेक्टर-70 के नामी बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में रोपड़ जेल से लाकर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अंसारी ने कहा कि मेरी सेहत ज्यादा ठीक नहीं है जिस पर कोर्ट ने उन्हें दोबारा रोपड़ जेल भेज दिया है। अब अंसारी को 12 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

अंसारी को व्हीलचेयर पर भारी पुलिस बल के साथ पिछले गेट से लाया गया। बड़ी बात यह रही कि मीडिया से बचकर अंसारी को यहां लाया गया। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। गौरतलब है कि अंसारी जनवरी, 2019 से रूपनगर की जिला जेल में बंद हैं। मोहाली के एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए अंसारी को यहां रखा गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार अंसारी को साथ ले जाने की मांग कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हर बार अंसारी की खराब सेहत को वजह बताया गया। अंसारी की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बताई गई है और उसे हाई लेवल शुगर भी है। मेडिकल बोर्ड के अनुसार इसी वजह से वह लंबा सफर नहीं करता। गौरतलब है कि अंसारी को लेकर पंजाब और यूपी सरकार में टकराव चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पंजाब सरकार अंसारी को बचा रही है।

पहले पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा, फिर मिला युवक का शव, शरीर पर चाकू से गोदने के निशाना

इमामगंज (गया)। गया जिले के इमामगंज प्रखण्ड की चुआवार पंचायत के दोनयां गांव के पास रमहरी आहार में बुधवार को एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक की पहचान इमामगंज प्रखण्ड के बभंडीह गांव के महजरी भुईयां के 30 वर्षीय बेटा गोविन्द भुईयां के रूप में हुई है। मृतक के भाई नंदलाल भुईयां ने बताया कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच सोमवार को झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद भाई गोविन्द भुईयां सोमवार को शाम में ही घर से निकल गया था। जिसे खोजबीन करने के लिए उसकी पत्नी ललिता देवी अपने रिश्तेदार के यहां खोजते हुए अपने नैहर दोनयां तक गयी। लेकिन, कहीं पर वह नहीं मिल सका। इसके बाद पत्नी शाम में वह अपने नैहर ही रुक गयी।

बुधवार को सुबह दोनयां गांव के बगल में रमहरी आहार में उसका शव मिला। मृतक के छोटे-छोटे चार बच्चें हैं। जिसमें तीन लड़का व एक लड़की है। बताया जाता है कि यूवक की हत्या चाकू व अन्य नुकीला सामान से गोदकर किया गया है। इसके बाद उसे आहार के पानी में फंकंकर छोड़ दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद इमामगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया भेज दी। घर के परिजन पत्नी व ससुराल वालों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाने में जुटी है।

इस सम्बंध इमामगंज एसएचओ पंकज कुमार ने बताया कि कोचया दोनयां आहार के पास रमहरी आहार से एक युवक शव मिला है। उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि हत्या चाकू व अन्य कुछ सामान से गोदकर किया गया है। लेकिन हत्या क्यों हुई, इसका पता नहीं चल सका है। घटना का छानबीन की जा रही है। इधर मंगलवार को देर शाम छकरबन्धा पंचायत के सरपंच गणेश पासवान के पुत्र की हत्या कर कुआं में डाल दिया गया था। उस घटना को पुलिस जांच ही कर रही थी कि 12 घंटे के भीतर दूसरे युवक की हत्या कर आहर में फेंक दिया जाना इमामगंज प्रखंड में होली के दौरान सनसनी फैल गई। लगातार हत्या की घटना घटने से पुलिस की भी नींद हराम हो गई है।

एक नजर

इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआइ अदालत से आखिरी तीन आरोपी भी बरी

अहमदाबाद । सीबीआइ की विशेष अदालत ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले में क्राइम ब्रांच के तीन अधिकारियों की ओर से की गई कार्यवाही को जायज ठहराया है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने आखिरी तीन आरोपी तरुण बारोट, जीएल सिंघल में अनाजों चौधरी को भी आरोप से मुक्त कर दिया है। गत दिनों तीनों ही अधिकारियों ने आरोपों से मुक्त करने की अर्जी लगाई थी। इससे पहले तत्कालीन महानिदेशक पीपी पांडे, तत्कालीन डीआइजी डी जी वंजारा व तत्कालीन पुलिस उपायुक्त एन के अमीन को भी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जी एल सिंघल, तरुण बारोट व अनाजों चौधरी ने आईबी से मिले इनपुट के आधार पर कार्यवाही की जैसा उन्हें करना चाहिए था।

अदालत ने यह भी कहा कि इशरत को आतंकवादी नहीं मानने का कोई कारण नजर नहीं आता है। पुलिस अधिकारियों ने जिस घटना को अंजाम दिया वह परिस्थिति जन्य थी तथा उनके द्वारा यह जानबूझकर किया गया हूं ऐसा नहीं लगता है। इशरत जहां व उसके तीन साथियों जावेद शेख, अमजद अली व जीशान जौहर को क्राइम ब्रांच ने जून 2004 में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे पूर्व आईपीएस एवं क्राइम ब्रांच के मुखिया डी जी बंजारा तथा पुलिस उपाध्यक्ष एनके अमीन को भी आरोपी बनाया गया था।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार की देर रात हुई सर्जरी, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में हुए थे भर्ती

मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का मंगलवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सर्जरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि डॉक्टरों ने सर्जरी कर उनके गॉल ब्लैडर में फंसे स्टोन को बाहर निकाल दिया है। शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार रात को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अमित मायादेव ने ऑपरेशन करने के बाद बताया, कुछ परीक्षण चलाने के बाद आज हमने उनकी (शरद पवार) पर सर्जरी करने का फैसला किया, क्योंकि कुछ जटिलताएं थीं। हम बाद में उनकी पित्ताशय की थैली हटाने का निर्णय लेंगे। वर्तमान में वह पूरी तरह से डॉक्टरी निगरानी में है।

80 वर्षीय शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां जांच रिपोर्ट में उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की बात पता चली थी। राकांपा नेता नवाब मलिक ने बताया कि पवार को उनके पूर्व निर्धारित ऑपरेशन से एक दिन पहले, मंगलवार को पेट में दर्द की शिकायत की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। नवाब मलिक ने रविवार शाम को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि शरद पवार पेट में दर्द से परेशान थे।

शरद पवार ने कहा था, वह खून पतला करने की दवाइयां लेते हैं, जिन्हें इस समस्या का पता चलने के बाद बंद कर दिया गया है। उन्हें 31 मार्च, 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जिसके बाद उनकी एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। इसे देखते हुए उनके आगामी कार्यक्रमों को रद कर दिया गया है। राकांपा नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है चिंता की कोई बात नहीं है।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नहीं लगेगा लॉकडाउन, वापस लिया गया फैसला

औरंगाबाद । महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मंगलवार (31 मार्च) रात से जो लॉकडाउन होने वाला था उसे अब रद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने पत्रकारों को बताया कि 31 मार्च से 9 अप्रैल तक जो लॉकडाउन होने वाला था उसे रद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इस संबंध में हमने गैर-सरकारी संगठनों, अन्य संगठनों, राजनीतिक संगठनों और सरकार के साथ भी चर्चा की थी जिसके बाद 31 मार्च रात 12 बजे से 9 अप्रैल तक लगने वाले लॉकडाउन को रद कर दिया गया है।

औरंगाबाद जिला कलेक्टर ने बताया के जन आक्रोश के कारण लॉकडाउन का रद किया गया है। संशोधित कोरोना गाइडलाइन भी जल्द लागू की जाएगी। बता दें कि औरंगाबाद में बुधवार को 10 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लागू होने वाला था और 9 अप्रैल तक लागू रखने का फैसला लिया गया था । इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई थी।

औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। बता दें कि औरंगाबाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में कोरोनोवायरस संक्रमणों की सबसे अधिक संख्या वाले 10 जिलों में से एक है। इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से कहा था कि वे अगले कुछ दिनों में राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें।

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से मंगलवार रात मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 27,918 नए मामले और 139 मौतें दर्ज की गई हैं। जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 27,73,436 तक पहुंच चुका है। राज्य में अब तक कुल 23,77,127 लोग इस महामारी के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 3,40,542 मरीज सक्रिय बताये गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 54,422 संक्रमितों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है।

नंदीग्राम सीट पर हार-जीत तय करेगा भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक अस्तित्व

कोलकाता । बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार अभियान मंगलवार शाम समाप्त हो गया। वोटिंग 1 अप्रैल को होगी। वहीं, इस चरण में सबसे हाईप्रोफाइल सीट पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम है। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हाल में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला है। विश्लेषकों की मानें तो यह चुनाव सुवेंदु अधिकारी के लिए काफी अहम है। यह उनके राजनीतिक अस्तित्व को तय करेगा। दरअसल, सुवेंदु ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। लगभग 14 साल पहले जबरन कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक संघर्ष में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया था। नंदीग्राम यानी पूर्व मिदनापुर जिले का कृषि प्रधान क्षेत्र, जहां साढ़े तीन दशक तक वाममोर्चा सत्ता पर काबिज रहा। भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी वर्ष 2011 में सत्ता में आई थीं। यहां के लोग ममता को दीदी और सुवेंदु अधिकारी को दादा पुकारते हैं। मगर चार महीने पहले यह क्षेत्र दीदी और दादा में बंट गया है।

दरअसल, सुवेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम का चुनाव उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए चुनौती बन गया है। इस चुनाव में अगर वह हारते हैं, तो यह उनके लिए तगड़ा झटका होगा। यही नहीं, भाजपा में भी उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवालिया निशान लग जाएगा। वहीं, अगर वह चुनाव जीतते हैं, तो बंगाल में वह भाजपा के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी और अधिक मजबूत हो जाएगी। ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी ही तेजी से अपनी छवि भूमि अधिग्रहण आंदोलन के समावेशी नेता से बदलकर हिंदुत्व के पैरोकार वाले नेता के रूप में कर ली है। अब वह दावा कर रहे हैं कि यदि वह चुनाव हारते हैं, तो तृणमूल नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बना देगा।

भाजपा में आए शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कहते हैं कि ममता ने शुभेंदु का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि वह उनके भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के लिए चुनौती बनकर उभरे थे। लेकिन हमें नंदीग्राम की जनता पर पूरा भरोसा है। यह न केवल शुभेंदु है बल्कि हमारे पूरे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु भी तृणमूल के असंतुष्ट सांसद हैं। अधिकारी और उनके पिता 1999 में तृणमूल में शामिल हो गए। उस समय तृणमूल के गठन को एक साल ही हुआ था। वर्ष 2007 में नंदीग्राम में हुए कृषि भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने बंगाल की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इस आंदोलन ने अधिकारी को तृणमूल के शीर्ष के नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि ममता ने कुछ और ही तय कर रखा था। दोनों नेताओं के बीच मतभेद के बीज उस समय पड़े जब 2011 के सत्ता में आने के बाद तृणमूल की पहली वार्षिक शहीद दिवस रैली में बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक की राजनीति में आने की घोषणा की।

अधिकारियों ने नागांव में असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की पूर्व संध्या पर एक वितरण केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और अन्य चुनाव सामग्री की जांच करते हुए।

राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव के लिए पांच अप्रैल तक देंगे जानकारी : आयोग

कोच्चि । चुनाव आयोग ने केरल हाई कोर्ट को बताया कि राज्य की मौजूदा विधानसभा के रहते राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव कराने के बारे में पांच अप्रैल तक अपने रुख की जानकारी देंगे।

आयोग ने कहा कि राज्यसभा में राज्य से तीन सीटें भरने के लिए 14वीं केरल विधानसभा के कार्यकाल के दौरान चुनाव कराए जाएंगे। आयोग के वकील के आग्रह पर विचार करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई पांच अप्रैल तय कर दी। सोमवार को चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव

प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

बता दें कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस संबंध में लिखित बयान सौंपने को कहा था। चुनाव आयोग ने राज्य विधानसभा और सत्ताधारी माकपा की ओर से दाखिल याचिका पर यह दलील सौंपी है। माकपा ने तीन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया टालने के आयोग के फैसले को चुनौती दी है।

बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को सिर्फ एक चरण में होंगे और चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित होंगे। 140 सीटों के लिए होने जा रहे इन चुनावों के लिए मुख्य मुकाबला सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले सत्तासीन गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ के बीच है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन पिछले 5 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को 91 सीटें, यूपीए को 47 सीटें और भाजपा को एक सीट मिली थी।

स्टार प्रचारकों की सूची में वसुंधरा को 5वें नंबर पर जगह मिली, गहलोत और पायलट आए एक मंच पर

जयपुर । राजस्थान भाजपा में खेमेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच एकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों को दिखावे के लिए साथ लाया जा रहा है। लेकिन उनके समर्थक विधायक और नेताओं के मन नहीं मिल पा रहे। प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को हो रहे उप चुनाव के लिए भाजपा ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची तय की है।

स्टार प्रचारकों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 5वें नंबर पर रखा गया है। सूची में पहले नंबर पर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह, दूसरे नंबर पर सह प्रभारी भारती बेन, तीसरे नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और चौथे नंबर पर विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को रखा गया है। प्रदेश से केंद्र में तीन मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन लाल मेघवाल और कैलाश चौधरी के साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव व ओमप्रकाश माथुर को भी रखा गया है। 30 नेताओं की सूची में वसुंधरा के समर्थकों में से एकमात्र पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को रखा गया है।

वहीं उनके कट्टर विरोधियों को सूची में जगह दी गई है। इनमें राष्ट्रीय मंत्री

अलका गुर्जर, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, विधायक राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर और जोगेश्वर गर्ग शामिल है। एक दिन पहले मंगलवार को तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन-पत्र दाखिल करने के बाद हुई सभा में वसुंधरा नहीं पहुंची, जबकि उनके विरोधियों के हाथों में पूरी कमान रही। सभाओं में लगे होर्डिंग्स में 10 नेताओं के फोटो लगाए गए, लेकिन वसुंधरा का नहीं लगाया गया। उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा को किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार अभियान की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। जबकि अधिकांश राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए अलग-अलग राज्यों में भेजा गया है। प्रदेश में पिछले दो साल से पार्टी की गतिविधियों से उन्हे लगभग दरकिनार किया जा रहा है। पूनिया और उनके समर्थक फैसले लेने में ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे, जिससे वसुंधरा को राजनीतिक नुकसान नहीं हो।

उधर, कांग्रेस में काफी कोशिश के बाद अजय माकन सीएम गहलोत व पायलट को एकमंच पर लाने में तो सफल रहे, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले। तीन में से दो सीटों पर गुर्जर वोटों की बहुलता को देखते हुए सीएम व पार्टी नेतृत्व को पायलट को साथ रखना जरूरी हो गया है। इस वजह से ही गहलोत और माकन पायलट को अपने साथ लेकर मंगलवार को सभाओं में गए। हालांकि दोनों के समर्थक विधायक व नेता एक-दूसरे से दूर ही नजर आ रहे हैं। गहलोत ने पायलट समर्थकों को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी नहीं सौंपी।

कांग्रेस के निशाने पर भाजपा सरकार, बिल की कॉपी उपलब्ध न कराने का लगा आरोप

अहमदाबाद । गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के उप सचेतक शैलेश परमार ने सरकार पर तीन बिल की कॉपी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया तो जवाब में गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि यह बिल अधिक महत्व के नहीं है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र अब अपने शेष 2 दिन में काफी हंगामेदार रहने वाला है। बुधवार को 8 सरकारी विधेयक पेश होने हैं लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में उप सचेतक शैलेश परमार ने कहा है कि सरकार ने विपक्ष को बिल की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है।

संसदीय प्रक्रिया एवं परंपरा के अनुसार सरकार की ओर से बिल पेश किए जाने के 3 दिन पहले विपक्ष को विदेश की कॉपी उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की ओर से उन्हें 8 में से 3 बिल उपलब्ध ही नहीं कराए गए। कांग्रेस पहले भी सरकार पर विधानसभा में मनमानी करने का आरोप लगाती रही है। भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस के निशाने पर इस बात को लेकर भी रहती है की सरकार सदन में संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करती है तथा विपक्ष को उसके संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित करती रही है। राज्य सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा सदन में बताया कि सरकार की ओर से बुधवार को 8 सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें से तीन विधेयक ऐसे हैं जो अधिक महत्व के नहीं हैं, उससे राज्य तथा अन्य विभागों पर कोई व्यापक असर नहीं पड़ने वाला है। उनका यह कहने का अर्थ यही है कि कम महत्व के बिल होने के कारण उन्हें विपक्ष को नहीं दिए गए।

उदयपुर में एक युवक ने खाना खिलाने से इंकार करने पर अपने भाई की ले ली जान

उदयपुर । यहां हिरणमगरी थाना अंतर्गत टेकरी क्षेत्र में एक युवक ने अपने मौसेरे भाई की जान इसलिए ले ली कि उसने उसे खाना खिलाने से इंकार कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार टेकरी क्षेत्र में आकाश गुर्जर अपने मित्र फारूख, नील तथा राजेंद्र के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के समीप नॉनवेज खाना पका रहा था। इसी बीच उसका मौसेरा भाई विकास पुत्र नरेश गुर्जर भी वहां आया और उसने भी खाना खिलाने के लिए बोला। जबकि आकाश ने विकास को खाना खिलाने से इंकार कर दिया और वहां से चले जाने को कहा।

इस बात पर विकास नाराज हो गया तथा उसने अपने मौसेरे भाई आकाश पर हाथ उठा दिया। जिस पर आकाश के दोस्तों ने विकास गुर्जर को पकड़ा तथा वह उससे समझा रहे थे। विकास ने एक बार आकाश को चेतावनी दी। आपसी कहासुनी के बीच अचानक विकास ने अपनी पेंट की जेब में रखा चाकू निकाला तथा विकास को घोंप दिया। जिससे आकाश लहूलुहान होकर सड़क पर गिया गया और विकास वहां से भाग निकला। आकाश को उसके दोस्त तत्काल महाराणा भूपाल अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर घटना की जानकारी हिरणमगरी थाना पुलिस और आकाश के परिजनों को लगी।

आकाश के मित्र नील पुत्र राजेंद्र गुर्जर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने हमलावर विकास की तलाश शुरू दी, जो एक घंटे में ही पुलिस लाइन के पीछे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थानाधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया कि हत्या के आरोपी विकास गुर्जर को दो दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि हत्या के आरोपी ने हमले में उपयोग लिया चाकू फैंक दिया था, जिसे बरामद किया जाना है। थानाधिकारी ने बताया कि विकास गुर्जर अपराधी प्रवृत्ति का युवक है तथा उसके खिलाफ पहले से चार मामले हिरणमगरी थाने में दर्ज हैं, उनमें से दो हत्या के प्रयास के हैं।

शिक्षित बेरोजगारों व संविदाकर्मियों को होगा लाभ, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दुर्घटना कवर

जयपुर । राजस्थान में बृहस्पतिवार से डेढ़ लाख संविदा कर्मियों को 10 फीसदी बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दो लाख से अधिक संविदाकर्मियों को लाभ होगा। रोजगार निदेशलय में पंजिकृत शिक्षित बेरोजगारों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब बेरोजगार युवकों को 4000, महिलाओं, ट्रासजेंडर्स व दिव्यांगों को 4500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले 3000 व 3500 भत्ता दिया जा रहा था।

प्रदेश में करीब 1.60 हजार बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा। ये वे हैं जिन्होंने रोजगार निदेशालय में पंजिकरण करा रखा है। जिन्होंने पंजिकरण नहीं करा रखा, उन्हे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देने को लेकर मुख्यमंत्री चिंरजीवी योजना भी बृस्पतिवार से ही शुरू होगी। योजना के तहत 1576 बीमारियों को कवर किया जाएगा। प्रदेश में बीयर की कीमतों में 30 से 35 रुपये की कमी होगी। नई आबकारी नीति में बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क एमआरपी में कमी की गई है।प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 30 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

सरकारी कर्मचारी 220 रुपये प्रतिमाह पर 3 लाख तक का बीमा, 700 रुपये प्रतिमाह पर 10 लाख तक का बीमा और 1400 रुपये प्रतिमाह पर 30 लाख तक के बीमाधन में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। नये वित्तीय वर्ष में बृहस्पतिवारसे एविएशन सिक्योरिटी बढ़ेगी। अब घरेलू उड़ानों में एवियन सिक्योरिटी फीस 200 रुपये होगी, वर्तमान में यह 160 रुपये है। केंद्र व राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के प्रावधान अब लागू होंगे। इनमें टेलीविजन और एयरकंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सहायक, भोजन बनाने वाले लांगरी,आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कूक कम हेल्पर, ग्राम रोजगार सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स सहित 14 विभागों व योजनाओं में संविदाकर्मी कार्यरत है ।

एनआइए ने मुंबई कोर्ट में कहा- मनसुख हत्याकांड के साजिशकर्ता के संपर्क में था सचिन वाझे

मुंबई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने दावा किया है कि मनसुख हिरेन हत्याकांड का आरोपित सचिन वाझे इसके साजिशकर्ता से लगातार संपर्क में था। एनआइए ने कोर्ट में कहा है कि वह जल्द ही इस हत्याकांड की साजिश एवं उद्देश्य का पता लगा लेगी। एनआइए के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले में वाझे किसी से लगातार निर्देश प्राप्त कर रहा था।

मनसुख हत्याकांड में गिरफ्तार विनायक शिंदे की हिरासत अवधि बढ़वाने के लिए जांच एजेंसी मंगलवार को एनआइए कोर्ट में गई थी। जांच एजेंसी का पक्ष रखते हुए वकील सुनील गोंजाल्विस ने कहा कि जब मनसुख हिरेन की हत्या की योजना बनी तो सचिन वाझे एवं विनायक शिंदे साथ-साथ मौजूद थे। इस दौरान मुंबई पुलिस का निलंबित एपीआइ वाझे मोबाइल फोन के जरिये इस मामले के साजिशकर्ता के संपर्क में था।

कोर्ट में दिए गए एनआइए के इस बयान से पता चलता है कि अंटीलिया प्रकरण एवं मनसुख हत्याकांड में सचिन वाझे के अलावा भी कोई साजिशकर्ता है, जिसके संपर्क में सचिन वाझे लगातार बना हुआ था। गोंजाल्विस ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी को हाल ही में कुछ डीवीआर, सीपीयू एवं लैपटाप मिले हैं। इसके अलावा कुछ सिमकार्ड की एक लिस्ट भी बरामत

हुई है। इन सामग्रियों के बारे में विनायक शिंदे एवं सचिन वाझे से पूछताछ की जानी है। इसलिए शिंदे की हिरासत अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

विशेष एनआइए कोर्ट के जज पीआर सितरे ने वकील के तर्कों से सहमत होते हुए विनायक शिंदे की हिरासत अवधि सात अप्रैल तक बढ़ा दी। हालांकि विनायक शिंदे के वकील गौतम जैन ने उसकी एनआइए हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उसे नौ दिन तक पहले ही हिरासत में रखा जा चुका है। इसलिए उसे अब और एनआइए की हिरासत में नहीं देना चाहिए।

गौतम जैन के अनुसार विनायक शिंदे की भूमिका सिर्फ वाझे को सिम कार्ड उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी। इसी प्रकार अहमदाबाद के क्रिकेट बुकी नरेश गोर के वकील ने भी गोर की भूमिका सिर्फ सिम कार्ड उपलब्ध कराने तक ही बताते हुए कहा कि उसे हत्या की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

बता दें कि एनआइए मनसुख हत्याकांड एवं उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के निकट खड़ी की गई विस्फोटक लदी स्कार्पियो, दोनों मामलों की जांच कर रही है। वह कोर्ट को बता चुकी है कि ये दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

एनआइए ने सचिन वाझे की एक और लक्जरी कार की बरामद

इन दोनों मामलों की जांच करते हुए ही एनआइए ने मंगलवार को नवी मुंबई से सचिन वाझे की एक और लक्जरी कार बरामद की। इस कार का उपयोग वाझे का एक सहयोगी कर रहा था। इसके अलावा दो दिन पहले मुंबई की मीठी नदी से मिलीं दो नंबर प्लेटों का मामला भी गहरा गया है। इनमें से एक नंबर प्लेट औरंगाबाद से पिछले साल चोरी हो गई थी। इसके मालिक विजय नाडे ने 17 नवंबर, 2020 को इस कार की चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन रविवार को जब एनआइए ने मीठी नदी में गोताखोरों को उतारकर सचिन वाझे द्वारा फिंकवाए गए सामान निकलवाए तो उसमें एक नंबर प्लेट ऐसी भी मिली, जो विजय नाडे की कार की थी। नाडे का कहना है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। लेकिन जहां आवश्यकता होगी, वह एजेंसी को सहयोग करेंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि की तबीयत बिगड़ी, कोरोना से हैं संक्रमित

मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को कमजोरी की शिकायत के बाद एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रश्मि ठाकरे कोरोना संक्रमित हैं इसकी पुष्टि 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। ठाकरे के परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक, रश्मि ठाकरे कमजोर महसूस कर रही थीं। नियमित जांच और बेहतर देखभाल के लिए उन्?हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री और रश्मि ठाकरे को 11 मार्च को ष्द्धड्ढद्धष्ठ-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे, आदित्य ठाकरे 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद दोनों को होम क्वारंटीन में रखा गया था। लेकिन मंगलवार को रश्मि ठाकरे की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और कमजोरी महसूस होने लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्?य में 27,918 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 139 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महानगर में कोरोना संक्रमण का डबलिंग रेट 50 दिन हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण यहां अब तक 600 से अधिक इमारतों को सील किया जा चुका है। राज्?य में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने की तैयारी का ऐलान किया था। लेकिन बीएमसी आयुक्?त आईएस चहल ने का कहना है कि यहां तत्?काल लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। अगले 15 दिनों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पार्टी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां शोवा मजुमदार की हत्या के विरोध में एक रैली में भाग लिया।

प्रभास ने खरीदी ड्रीम कार, हैदराबाद की सड़कों पर फर्राटे लगाकर दौड़ी 6 करोड़ की गाड़ी

'बाहुबली' फेम साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने अपना एक और सपना पूरा कर लिया है। प्रभास के लग्जरी गाड़ियों के काफिले में उनकी ड्रीम कार लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस रोडस्टर शामिल हो गई है। प्रभास ने फैन पेज ने कुछ वीडियोज शेयर किए हैं, जिसमें वह अपनी चमचमाती नई कार से हैदराबाद की सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। प्रभास की इस नई कार की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। प्रभास लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं। उनकी इस नई कार की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 करोड़ रुपये है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज सामने आए हैं, उनमें से एक में प्रभास अपनी ड्रीम कार से कवर हटा रहे हैं, जबकि दूसरे में हैदराबाद की सड़कों पर कार दौड़ा रहे हैं। प्रभास ने ऑरेंज कलर की लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस रोडस्टर खरीदी है। खास बात यह भी है कि प्रभास ने यह कार अपने पिता सूर्या नारायण राजू की बर्थ ऐनिवर्सरी पर खरीदी है। प्रभास की लग्जरी गाड़ियों के काफिले में 1.25 करोड़ रुपये की जगुआर एक्सजे के अलावा 8 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, 50 लाख की बीएमडब्ल्यू एक्स-3, 4 करोड़ की रेंज रोवर और 30 लाख की सेडान कार स्कोडा सुपर्ब भी शामिल हैं। प्रभास लंबे समय से स्पोर्ट्स कार खरीदने का मन बना रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट में एक और चीज पा ली है। वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रभास इन दिनों अपनी फिल्म 'राधे श्याम' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जबकि वह 'आदिपुरुष' और 'सलार' की भी शूटिंग में भी व्यस्त हैं। 'आदिपुरुष' में प्रभास के साथ कृति सैनन और सनी सिंह भी हैं। सैफ अली खान इस फिल्म में 'लंकेश' के रूप में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। जबकि प्रभास फिल्म में 'राम' और कृति 'सीता' के किरदार में होंगी।

अक्षय कुमार ने शेयर किया 'राम सेतु' से अपना फर्स्ट लुक, शूटिंग हुई शुरू

पिछले काफी समय से अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'राम सेतु' का फी चर्चा में है। अब इस फिल्म से अक्षय कुमार ने अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियॉलजिस्ट (पुरातत्वविद) का किरदार निभाने जा रहे हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच बने राम सेतु की सच्चाई का पता लगा रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा नजर आने वाली हैं। पिछले हफ्ते ही फिल्म का मूहूर्त शॉट अयोध्या में लिया गया गया था। हालांकि अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही शुरू करने वाले हैं। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे लिए सबसे खास फिल्म की शूटिंग का सफर आज से शुरू हो गया। राम सेतु की शूटिंग शुरू हो गई है। मैं इसमें एक आर्कियॉलजिस्ट का किरदार निभा रहा हूं। इस लुक पर आपके विचार सुनना पसंद करूंगा। यह मेरे लिए हमेशा मायने रखता है।' बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा करने जा रहे हैं। फिल्म कि क्रिएटिव प्रड्यूसर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी हैं।

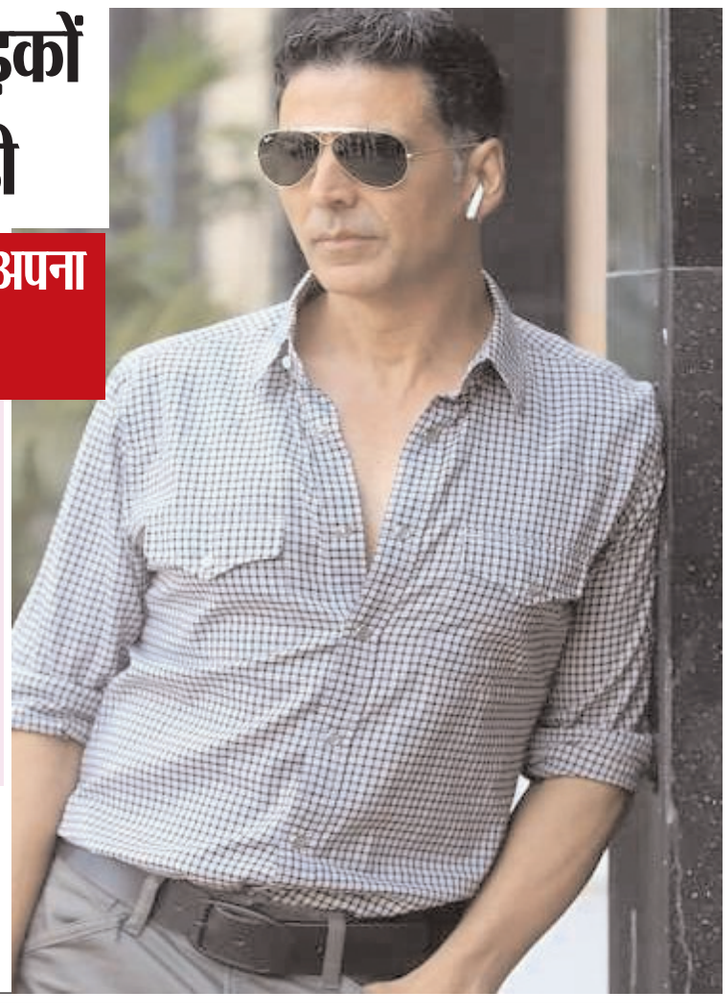

सतीश कौशिक की बेटी हॉस्पिटल में, बोले- रोने की आवाज सुनकर दिल टूट जाता है

बॉलिवुड ऐक्टर और फिल्ममेकर सतीश कौशिक पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब सतीश कौशिक की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है जिसके बाद वह हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। हालांकि यह अभी भी उनके लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनका परिवार और उनकी बेटी वंशिका अभी भी हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं। हालांकि अब सतीश की बेटी वंशिका की रिपोर्ट भी अब निगेटिव आ गई हैं। एक हालिया इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने कहा, 'मैं रिकवर हो रहा हूं और कुछ और दिन घर में क्वॉरेंटीन रहूंगा। लेकिन मेरी बेटी वंशिका अभी भी पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में है। उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ गई है मगर उसका बुखार नहीं जा रहा है। प्लीज उसके लिए दुआ करें। इस पर बात करते हुए सतीश ने आगे कहा, 'यही मुद्दा है। दरअसल कोविड के बारे में कुछ बी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अभी भी हालत खराब है। वंशिका कोविड निगेटिव आ गई है मगर फिर भी बीमार है। उसे काफी बुखार है और जब मैं उसके रोने की आवाज फोन पर सुनता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। दुआ करता हूं कि ऐसे कठिन समय पर भगवान अपने बच्चों का ख्याल रखे।' बता दें कि पिछले कुछ ही दिनों में बॉलिवुड के बहुत से सिलेब्रिटीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

इनमें रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, विक्रांत मैसी, कार्तिक आर्यन, फातिमा सना शेख, वरुण धवन, कृति सैनन जैसे बहुत से नाम शामिल हैं। हालांकि इनमें से लगभग सभी ने कोरोना को सफलतापूर्वक मात दे दी है जबकि कुछ लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं।

फातिमा सना शेख को भी हुआ कोरोना, घर में हुई क्वॉरेंटीन

बॉलिवुड में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले सिलेब्रिटीज की संख्या में इजाफा हो रहा है। कई बड़े सिलेब्रिटीज के बाद सोमवार को ऐक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। फातिमा ने सोशल मीडिया पर यह सूचना अपने फैन्स के साथ शेयर की है और बताया है कि वह डॉक्टर्स की बताई सारी सलाह फॉलो कर रही हैं। फातिमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बारे में बताया है। फातिमा ने लिखा, 'मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हूं और फिलहाल सारी सावधानियां और नियम कायदों का पालन करते हुए मैंने खुद को अपने घर में क्वॉरेंटीन कर लिया है। आप सभी की चिंताओं और दुआओं के लिए शुक्रिया। कृपया सुरक्षित रहने का प्रयास करें।' फातिमा ने पहले हाल के दिनों में आमिर खान, मनोज बाजपेयी, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, सतीश कौशिक, परेश रावल, मिलिंद सोमन जैसे बहुत सारे बॉलिवुड कलाकार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

शेरॉन का बचपन में यौन शोषण करते थे नाना, वाजिना शॉट के बाद किया एक और खुलासा

कुछ दिनों पहले ही हॉलिवुड की मशहूर फिल्म 'बेसिक इंस्टिंक्ट' में काम कर चुकी ऐक्ट्रेस शेरॉन स्टोन ने बताया था कि किस तरह हॉलिवुड में उन्हें हैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। शेरॉन ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी हैं और इसमें उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि बचपन में उनके नाना ने भी उनका यौन शोषण करने का प्रयास किया था। शेरॉन ने अपने संस्मरण 'द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस' में और भी चैंकाने वाले खुलासे किए हैं। शेरॉन ने अपनी किताब में बताया है कि जब वह केवल 11 साल की थीं तब उनके नाना क्लैरेंस लॉसन उनके साथ छेड़खानी किया करते थे। उन्होंने लिखा है कि उनके नाना केवल उनके साथ ही नहीं बल्कि उनकी बहन केली के साथ भी ऐसा ही करते थे। शेरॉन ने अपने संस्मरण में एक और चैंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उनके और बहन केली के यौन शोषण में उनकी नानी ही नाना की मदद किया करती थीं। शेरॉन ने बताया है कि उनकी नानी दोनों बहनों को नाना के साथ अकेले एक कमरे में बंद कर दिया करती थीं ताकि वह आराम से उनके साथ छेड़खानी कर सकें।

पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क दुर्घटना में मौत, तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर

मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजान की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। 31 साल के दिलजान की कार मंगलवार सुबह को अमृतसर के निकट जांडियाला गुरु में हादसे का शिकार हो गई। दिलजान अमृतसर से करतारपुर के लिए जा रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में टक्कर मार दी। दिलजान की मौका-ए-वारदात पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, कार और ट्रक में सीधी टक?कर हुई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दिलजान को आनन-फानन में नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिलजान की पत्नी और उनके बच्चे कनाडा में रहते हैं। अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर दिलजान की कार ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में टक्कर मारी। कार में सिंगर अकेले ही थे। वह अमृतसर से अपने होमटाउन करतारपुर जा रहे थे। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सिंगर की कार की रफ्तार बहुत तेज दी। ऐसे में जब टक्कर हुई तो कार पलट गई। दिलजान की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। दिलजान की मौत की खबर पाते ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में हर कोई सकते में है। सोशल मीडिया पर कई दिग्गजों ने दिलजान की मौत पर दुख जताया है। दिलजान पहली बार चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने 2012 में सिंगिंग रियलिटी शो 'सुर क्षेत्र' में हिस्सा लिया था। दिलजान को उनके पंजाबी गीतों के लिए शो में खूब पसंद किया गया था। उन्होंने कई भजन भी गाए थे और 'आवाज पंजाब दी' में भी हिस्सा लिया था।

रिया चक्रवर्ती ने शेयर की तस्वीर, प्यार पर लिख दी बड़ी बात

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उनकी यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है। बता दें कि बीते सात महीने में उनकी ये दूसरी पोस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि वह अपनी एक दोस्त के साथ लेटी हुई हैं और हाथ से दिल बनाती हुई नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने लिखा, 'प्यार एक ताकत है। प्यार एक ऐसा कपड़ा है, जो कभी भी फीका नहीं पड़ता। भले ही आप इसे कितनी भी बार पानी से धो लें।' बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़े ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती चर्चा में आ गई थीं। एनसीबी ने उन्हें और उनके भाई को गिरफ्तार किया था। जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा किया गया था। वर्कफ्रंट की बात करें तो रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर रूमी जाफरी की फिल्म 'चेहरे' में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी भी दिखाई देंगे। फिल्म ट्रेलर में तो रिया चक्रवर्ती की झलक दिखी लेकिन फिल्म के पोस्टर और टीजर से वह गायब थीं।

कंगना रनौत ने फिर साधा करण जौहर पर निशाना, सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू की तारीफ

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत ने सबसे पहले प्रड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर पर नेपोटिजम का आरोप उनके टॉक शो 'कॉफी विद करण' में लगाया था। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत लगातार नेपोटिजम के लिए करण जौहर को टारगेट कर रही हैं। अब एक बार फिर सिमी ग्रेवाल के बहाने कंगना ने करण जौहर की तीखी आलोचना की है। दरअसल कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म 'थलाइवी' में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभा रही हैं। जयललिता का इंटरव्यू काफी पहले सिमी ग्रेवाल ने अपने टॉक शो में लिया था जो काफी मशहूर भी हुआ था। एक ट्विटर यूजर ने इस इंटरव्यू की तारीफ में लिखा, 'मैं अभी सिमी ग्रेवाल का इंटरव्यू देख रही हूं और मुझे नहीं लगता है कि कोई इससे बेहतर इंटरव्यू ले सकता है। आजकल के शोज में ऐसी ईमानदारी नहीं होती है। इनका शो काफी भरोसेमंद और मजेदार है।' कंगना ने इसी ट्वीट के जवाब में एक तीखा ट्वीट किया है।

कंगना रनौत ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, 'हां, कंगना रनौत ने सही मायने में एक सिलेब्रिटी का वास्तविक रूप पेश किया है। जया मां के साथ उनके इस इंटरव्यू ने मेरी रिसर्च में काफी मदद की। यह सब कुछ पापा जो के इंटरव्यू के बारे में नहीं कहा जा सकता जो दूसरों की बुराई, गॉसिप और फ्रस्ट्रेटेड सेक्स के बारे में होते हैं।' बता दें कि सिमी ग्रेवाल ने अपने टॉक शो की शुरूआत 1997 में की थी। इस शो के 5 सीजन में वह बॉलिवुड की लगभग सभी बड़ी हस्तियों सहित बहुत से राजनीति से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू ले चुकी हैं। करण जौहर का शो इसके काफी बाद 2004 में शुरू हुआ था। अभी तक इसके 6 सीजन आ चुके हैं जिसमें वह कंगना रनौत सहित सभी बड़े बॉलिवुड सितारों का इंटरव्यू ले चुके हैं।

चेतेश्वर पुजारा बोले- आईपीएल में वापसी करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है

नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के स्पेशलिस्ट बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा को आइपीएल 2021 के लिए नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था। सीएसके ने उनको एक करोड़ रुपये की बेस प्राइस में खरीदा था। लंबे समय के बाद उनकी आइपीएल में वापसी हो रही है। सात साल के बाद वे आइपीएल खेलते नजर आएंगे। उन्होंने हाल ही में अपनी सफेद गेंद की वापसी और टी20 टूर्नामेंट की तैयारियों के बारे में क्रिकबज से बात की। अपने आखिरी आइपीएल मैच के बारे में बताते हुए पुजारा ने कहा, यह सुनिश्चित है कि लंबे समय से मैंने नहीं खेला है। मैं किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) का आखिरी हिस्सा था। मेरा आखिरी खेल, मुझे लगता है 2014 में वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ था। आइपीएल में वापसी करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह दुनिया की सबसे अच्छी लीग है और मैं काफी समय से इसका हिस्सा बनने से चूक गया हूं।

वहीं, जब उनसे ये पूछा गया कि जब आपको सीएसके ने खरीदा था तो सभी फ्रेंचाइजियों ने तालियां बजाई थीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं अधिक प्रसन्न नहीं हो सकता था। मैं फ्रेंचाइजियों के उस इशारे पर वास्तव में गर्व महसूस कर रहा हूं और प्रसन्न हूं। यह देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलने वाला सम्मान है। मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं फ्रेंचाइजी, श्रीनिवासन और माही भाई (एमएस धोनी) को धन्यवाद देता हूं। सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन नए एक बयान में कहा था कि वे उन्हें आइपीएल की नीलामी में अनसोल्ड नहीं रहने देना चाहते थे, क्योंकि वे नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत को टेस्ट सीरीज जिताई थी। इसको लेकर उन्होंने कहा, उनका यह कहना बहुत ही अच्छा है।

आईपीएल 2021 के लिए आरसीबी ने ट्रेनिंग की शुरू, आज टीम से जुड़ेंगे विराट कोहली

चेन्नई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने नौ अप्रैल से शुरू होने वाले आइपीएल के आगामी सत्र की तैयारियों के अंतर्गत यहां नौ दिवसीय अनुकूलन शिविर शुरू किया। टीम के कप्तान विराट कोहली गुरुवार को टीम से जुड़ेंगे। उनके भी अनिवार्य क्वारंटाइन में रहने की संभावना है। स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल, तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और मुहम्मद सिराज सहित 11 खिलाड़ियों ने क्रिकेट परिचालन निदेशक माइक हेसन और मुख्य कोच साइमन कैटिच के मार्गदर्शन में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। टीम के अन्य खिलाड़ी अपना सात दिन का क्वारंटाइन समाप्त होने के बाद शिविर से जुड़ेंगे। फ्रेंचाइजी ने कहा कि टीम का चेन्नई में नौ दिवसीय अनुकूलन शिविर शुरू हो गया है। शिविर सभी खिलाड़ियों को अनुभवी कोचों और स्टाफ जैसे संजय बांगर, श्रीराम श्रीधरन, एडम ग्रिफिथ, शंकर बासु और मालोलान रंगराजन के साथ काम करने का मौका प्रदान करेगा आरसीबी नौ अप्रैल को अपने अभियान की शुरुआत गत विजेता मुंबई इंडियंस के खिलाफ एम ए चिदंबरम स्टेडियम में करेगी।

जोफ्रा आर्चर के हाथ की सर्जरी हुई है। ऐसे में आइपीएल में नहीं खेल पाएंगे और उनकी गैरमौजूदगी में साउथ अफ्रीका के क्रिस मौरिस अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आइपीएल की नीलामी में बिके सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक क्रिस मौरिस ने कहा कि आगामी सत्र में आर्चर की अनुपस्थिति में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, लेकिन इससे टीम में उनकी भूमिका में कोई बदलाव नहीं होगा। मौरिस ने कहा, मैं आइपीएल में जिस भी टीम के लिए खेला हूं। मेरी भूमिका नई गेंद और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। टीम में हमेशा तेज गेंदबाज मिले हैं और मैं इसमें सहायक की भूमिका निभाता हूं।

न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 में 28 रन से हराया, सीरीज पर कब्जा

नेपियर। न्यूजीलैंड ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश को 28 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से बाधित मुकाबले में 17.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन का स्कोर खड़ा करने में कामयाबी पाई। इसके बाद बांग्लादेश के सामने 16 ओवर में 171 रन का संशोधित लक्ष्य रखा गया था। 7 विकेट के नुकसान पर टीम 142 रन ही बना पाई। तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में जीत हासिल कर 1-0 की बढ़त बनानने वाली न्यूजीलैंड ने दूसरा मैच जीत अंतर को 2-0 कर सीरीज अपने नाम कर ली। बारिश से बाधित डकवर्थ लुईस नियम के विवादों के बीच न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा सीरीज पर कब्जा जमाया। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स के 31 गेंदों पर नाबाद 58 रन की मदद से 18वें ओवर तक पांच विकेट पर 173 रन बना लिए थे, तभी बारिश आ गई और खेल रोकना पड़ा।

बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम से जीत के लिए 16 ओवर में 170 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन सौम्य सरकार (51) के अर्धशतक के बावजूद टीम सात विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इस तरह न्यूजीलैंड ने इस सत्र में घरेलू सरजमीं पर सातवीं सीरीज अपने नाम की, इसमें से चार टी-20, दो टेस्ट और एक वनडे सीरीज है। मैच रेफरी जैफ क्रो के आधिकारिक रूप से संशोधित लक्ष्य तय करने से पहले ही बांग्लादेश ने खेलना शुरू कर दिया। अंपायरों ने 1.3 ओवर में मैच रोका, जो नए लक्ष्य की आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे थे। क्रो अपने कम्प्यूटर पर गणना कर रहे थे जिससे काफी विलंब हुआ।

आईपीएल में 5वें सबसे युवा कप्तान बने पंत

दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्यों अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं ऋषभ

नई दिल्ली। 23 साल के ऋषभ पंत IPL के 14वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते दिखेंगे। वे IPL में कप्तानी करने वाले पांचवें युवा प्लेयर हैं। इससे पहले विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ने 22 साल और श्रेयस अय्यर और सुरेश रैना ने 23 साल की उम्र में अपनी-अपनी टीम की कप्तानी की है।

पंत को कप्तान बनाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता

कुछ बेहतरीन सीरीज की वजह से पंत का आत्मविश्वास अभी बढ़ा है। पिछले 4 महीनों में पंत अपने गेम को अलग ही लेवल पर ले गए हैं। पहले तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में सुधार किया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ विकेटकीपिंग स्किल्स से सबका दिल जीत लिया। उनके ट्रांसफॉर्म होने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी टीम के खिलाफ नवंबर में हुए प्रैक्टिस मैच से हुई। इस मैच में पंत ने शतक जड़ा था।

इसके बाद सिडनी टेस्ट में उन्होंने लगभग हारे हुए मैच को ऑस्ट्रेलिया के कब्जे से निकालकर भारत की ओर मोड़ दिया। सिडनी में चौथी पारी में जहां बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल था, वहां वे 118 गेंद पर 97 रन बनाकर आउट हुए और यह मैच ड्रॉ रहा। जो काम वे सिडनी टेस्ट में नहीं कर पाए, वह काम उन्होंने ब्रिस्बेन के गाबा में हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में कर दिया। गाबा में पंत चौथी पारी में 138 गेंदों पर 89 रन बनाकर नाबाद रहे। इसकी बदौलत भारत ने 32 साल बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था। जब वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गए थे, तो उन्हें टीम में विकल्प विकेटकीपर के तौर पर देखा जा रहा था।

जब वे वापस आए तो वे देश के सबसे पॉपुलर बल्लेबाज बन चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में उनके विकेटकीपिंग की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद इंग्लैंड के पिछले महीने हुए टेस्ट सीरीज में टर्निंग ट्रैक पर उन्होंने विकेट के पीछे कई शानदार कैच और स्टंप्स किए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने दर्शाया कि वे अब एक मैच्योर प्लेयर बन चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में लगाया गया शतक (101 रन) यह बताने के लिए काफी था कि वे कंडीशन को पढ़ने और उसके मुताबिक बल्लेबाजी करने में महारत हासिल कर चुके हैं।

एश्ले बार्टी सेमीफाइनल में पहुंचीं

मियामी ओपन जीतने से अब सिर्फ दो कदम दूर

नई दिल्ली। विश्व की नंबर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश्ले बार्टी मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बेलारूस के आर्यना सबालेंका को 6-4,6-7 (5), 6-3 से मात दी। अब सेमीफाइनल में उन्हें पांचवीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से भिड़ना होगा। बीते साल कोरोना वायरस की वजह से प्रतियोगिता रद्द करनी पड़ी थी। 2019 में मियामी ओपन जीतने वाली बार्टी इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मुकाबले जीत चुकी हैं। दूसरी ओर पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीय डेनियल मेदवेदेव ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके अंतिम चार में जगह बनाई। बार्टी ने सातवीं वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को 6-4, 6-7 (5), 6-3 से हराया। यह पिछले चार मैचों में तीसरा अवसर है जबकि उन्होंने तीन सेट में जीत दर्ज की। मेदवेदेव ने हालांकि फ्रांसिस टिफोउ को आसानी 6-4, 6-3 से पराजित किया। अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा ने पांचवीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीनी खिलाड़ी डिएगो श्वार्टजमैन को 6-3, 4-6, 7-5 से हराकर उलटफेर किया। एक अन्य मैच में रूस के आंद्रेई रूबलेव ने मारिन सिलिच को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में बार्टी सेमीफाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त इलिना स्वितोलिना से भिड़ेगी जिन्होंने अनास्तेसिया सेवास्तोवा को 6-3, 6-2 से हराया। जॉन इसनर ने एक मैच प्वाइंट गंवाया और आखिर में राबर्टो बातिस्ता आगुट ने उन्हें 6-3, 4-6, 7-6 (7) से पराजित किया। सेमीफाइनल में मेदवेदेव और आगुट आमने सामने होंगे।

एफआईएच प्रो लीग: अर्जेंटीना के खिलाफ मनप्रीत को कमान

रुपिंदर और वरुण की टीम में वापसी

अर्जेंटीना। मनप्रीत सिंह ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ अगले महीने होने वाले एफआईएच (अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ) प्रो लीग मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। मनप्रीत निजी कारणों से हाल में यूरोप दौरे पर नहीं गए थे। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह और वरुण कुमार की भी टीम में वापसी हुई है। वे चोटिल होने के कारण पिछले दौरे पर नहीं जा पाए थे।

हॉकी इंडिया ने 22 सदस्यीय टीम घोषित की है जो ब्यूनस आयर्स में 11 और 12 अप्रैल को अर्जेंटीना सामना करेगी। टीम बुधवार को रवाना होगी। भारत इसके अलावा जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के सिलसिले में अर्जेंटीना के खिलाफ छह व सात अप्रैल और 13 व 14 अप्रैल को अभ्यास मैच भी खेलेगा। टीम में गोलकीपर पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, बीरेंद्र लकड़ा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राज कुमार पाल, नीलकांत शर्मा, शमशेर सिंह, गुरजंत सिंह, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, जसकरण सिंह, सुमित और शैलानंद लाकड़ा को रखा गया है।

इन्हें मिला आराम: अनुभवी आकाशदीप सिंह, रमनदीप सिंह और सिमरनजीत सिंह को विश्राम दिया गया है।

हम 22 खिलाड़ियों की टीम लेकर जा रहे हैं। यह टोक्यो ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को अनुभव दिलाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका देने के बीच संतुलन बनोन्का प्रयास है।
ग्राहम रीड, मुख्य कोच

अफ्रीकन कप क्वालीफायर रद्द: विवादित कोविड परीक्षण के कारण लिया गया फैसल

नई दिल्ली। बेनिन के पांच खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से ठीक पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव घोषित किए जाने के विवादास्पद मामले के बाद उसका सिएरा लियोन के खिलाफ होने वाला अफ्रीकन कप नेशंस फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वालीफाईंग मैच रद्द कर दिया गया।

क्वालीफाईंग के लिहाज से यह महत्वपूर्ण मैच था। सिएरा लियोन को इसमें जीत की जरूरत थी जबकि बेनिन को केवल ड्रा की दरकार थी। इनमें से कोई भी एक टीम अगले साल कैमरून में होने वाले टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली 24वीं टीम बनती। फ्रीटाउन में होने वाले मैच के शुरू होने से ठीक पहले परीक्षणों के पॉजिटिव पाए जाने की घोषणा की गई। मैच शुरू होने के दो घंटे बाद भी जब बेनिन की टीम नहीं पहुंची तो सिएरा लियोन फुटबॉल संघ ने घोषणा की कि मैच को रद्द कर दिया गया है और इसके भविष्य का फैसला अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ करेगा।

बुमराह फिटनेस पर दे रहे हैं ध्यान

आईपीएल के लिए तेज गेंदबाज मुंबई इंडियंस से जुड़े, क्वारैंटाइन के दौरान कर रहे वेट ट्रेनिंग

मुंबई। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के बाद आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं। वे क्वारैंटाइन के दौरान अकेले रूम में अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने होटल के कमरे में वर्कआउट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह वेट उठाते नजर आ रहे हैं।। आईपीएल का 14 वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होना है। ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है।

बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद बायो-बबल से बाहर हो गए थे। वे 15 मार्च को स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंधे। बायो-बबल छोड़ने के कारण कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें एक हफ्ते क्वारैंटाइन पर रहना होगा। साथ ही उन्हें कई कोरोना जांच से गुजरना होगा।

बुमराह ने पिछले सीजन में मुंबई के लिए थे 27 विकेट

बुमराह ने UAE में हुए पिछले सीजन में मुंबई के लिए खेले 15 मैचों में 27 विकेट लिए थे। 14 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन था। उनकी इकोनॉमी भी 6.50 के आस-पास थी। उन्होंने IPLमें खेले अब तक 92 मैच में 109 विकेट लिए हैं। मुंबई की टीम पिछले सीजन की चैम्पियन थी। उसने सबसे ज्यादा 5 बार IPLका खिताब जीता है।

रोहित, पंड्या ब्रदर्स और सूर्यकुमार भी टीम से जुड़े

टीम के कप्तान रोहित शर्मा, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, उनके भाई क्रुणाल पंड्या और बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव सोमवार को मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए हैं। ये चारों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के हिस्सा थे। रविवार को पुणे में खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर 2-1 से जीत दर्ज की।

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर कप्तान रोहित शर्मा के मुंबई पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया है। इससे पहले उसने हार्दिक, क्रुणाल और सूर्यकुमार के मुंबई टीम से जुड़ने का वीडियो पोस्ट किया।

शूटिंग विश्व कप: पुरुष-महिला ट्रैप टीम को भी स्वर्ण, विश्व कप में श्रेष्ठ प्रदर्शन

मुंबई। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में पुरुष और महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने विश्व कप में अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। इसके साथ ही भारत ने कुल 15 स्वर्ण, नौ रजत और छह कांस्य पदकों के साथ शूटिंग विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को अंजाम दिया।

भारत की महिलाओं ने ट्रैप टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारत की तरफ से श्रेयांशी सिंह, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी ने टीम ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण जीता। फाइनल में भारतीय महिलाओं ने कजाकस्तान की टीम को 6-0 से चित किया। भारतीय टीम ने कजाखस्तान की मारिया दिमित्रियेंको, आईजान दोशमागेमबेतोवा, सारसेंकुल रिसबेकोवा को 6-0 से परास्त किया। वहीं ट्रैप की पुरुष स्पर्धा में काइनन चेन्नई, पृथ्वीराज थोंडाईमान और लक्ष्य की टीम ने स्लोवाकिया के माइकल स्लेमका, एड्रियन ड्रोब्नी और फिलिप मारीनोव को 6-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

भारतीय बॉक्सिंग पर कोरोना का साया: तुर्की दौरे पर 8 इंडियन बॉक्सर कोरोना पॉजिटिव

सभी को इस्तांबुल में क्वारैंटाइन किया गया

तुर्की। तुर्की दौरे पर गई इंडियन बॉक्सिंग टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को इस्तांबुल में क्वारैंटाइन किया गया। सूत्रों के मुताबिक, कोच धर्मेन्द्र यादव और संतोष बीरमोल के अलावा फिजियो शिखा केडिया और डॉ. उमेश, वीडियो एनालिस्ट नितिन कुमार को आइसोलेशन में भेजा गया है। तीन बॉक्सर गौरव सोलंकी (57 किग्रा), प्रयाग चौहान (75 किग्रा) और बृजेश यादव (81 किग्रा) एक हफ्ते पहले संक्रमित पाए गए थे। उनका टूर्नामेंट 19 मार्च को खत्म हो गया था। इसके बावजूद उन्हें क्वारैंटाइन में रहना पड़ रहा है। यह तीनों कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं।

टूर्नामेंट में भारत ने 2 मेडल जीते

इस्तांबुल में हुए बोसफोर्स टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ दो मेडल जीते। यह दोनों कांस्य हैं। एक मेडल पुरुष वर्ग में गौरव सोलंकी (57 किग्रा) ने जीता, जबकि दूसरा वुमन्स कैटेगरी में निकहत जरीन (51 किग्रा) हासिल किया।

निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही छुट्टी मिलेगी

तुर्की दौरे पर जाने वाले पुरुष मुक्केबाजों में ललित प्रसाद (52 किग्रा), शिव थापा (63 किग्रा), दुर्योधन सिंह नेगी (69 किग्रा), नमन तंवर (91 किग्रा) और कृष्णन शर्मा (91 किग्रा से अधिक) शामिल थे। वुमन्स इवेंट में जरीन, सोनिया लाथेर (57 किग्रा), परवीन (60 किग्रा), ज्योति ग्रेवाल (69 किग्रा) और पूजा सैनी (75 किग्रा) शामिल रहीं। इन सभी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इन सभी का 7 दिन क्वारैंटाइन रहने के दौरान दोबारा टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही छुट्टी मिलेगी।

कोहली के इस बड़े सुझाव पर बीसीसीआई नहीं करना चाहती विचार

मुंबई। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज के पहले मैच से पहले, भारत के कप्तान विराट कोहली ने खिलाड़ियों को उस लूप में रखने की आवश्यकता के बारे में बात की थी, जब खेलों के शेड्यूल की बात आती है, क्योंकि बायो-बबल में जीवन को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) का मानना है कि मौजूदा परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को फिर से तैयार करना सभी हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मुश्किल है।

एएनआइ से बात करते हुए बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा है कि विराट कोहली की चिंता जायज है, लेकिन शेड्यूल को बदलने से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड भी कोविड 19 महामारी से लड़ रहा है। अधिकारी ने कहा, यह एक वैध चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन वैकल्पिक बहुत बड़ी चिंताओं को बढ़ाएगा। इसे दो तरह से संबोधित किया जा सकता है। पहला यह है कि रोटेशन नीति बनाई जाए, जिससे खिलाड़ियों को डाउन-टाइम के लिए कुछ स्वतंत्रता मिल सके। ईसीबी का उदाहरण लें जहां जो रूट केवल लाल गेंद वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि उनके कैलिबर का खिलाड़ी सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा।

दूसरा अंतरराष्ट्रीय खेलों की कम संख्या को शेड्यूल करना है। इनमें से किसी भी मार्ग का निष्पादन उतना सरल नहीं है। यह पूछे जाने पर कि यह एक समस्या कैसे हल होगी तो इस पर अधिकारी ने कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया, जो सामने आएंगे और जो वास्तव में घरेलू क्रिकेटरों की वित्तीय स्थिति को चोट पहुंचा सकता है। यह कुछ ऐसा है जिसे बीसीसीआइ सीओए के युग के बाद संबोधित करना चाहता है। बीसीसीआइ का मानना है कि एक अच्छी संरचना वह है, जिसमें घरेलू खिलाड़ियों को करियर विकल्प के रूप में खेल को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। बोर्ड के अधिकारी ने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने भी कई विकल्प बंद कर दिए हैं।

अधिकारी ने कहा, सबसे पहले, मान्यताओं के विपरीत, बीसीसीआइ का धन असीम नहीं है। दूसरा, घरेलू क्रिकेटरों का स्टॉक अधिक मात्रा में ध्यान देने योग्य है, खासकर जब लगभग तीन साल पहले किए गए खिलाड़ी भुगतानों की समीक्षा का परिणाम काफी अलग था। तीसरा, राज्य संघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनके पास अपने क्षेत्रों में खेल को विकसित करने के लिए एक कठिन कार्य है, जो उन्होंने पहले नहीं किया था और यह मौजूदा संघों के अतिरिक्त है जो अपने स्वयं के मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे आगे बढ़ाने का जिम्मा भी बोर्ड का है।